कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक
प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिवशक्ति बक्सी

संपादक मंडल
सत्यपाल
संजीव कुमार सिन्हा

कला संपादक
धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क
वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क
lnL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QSDl : +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी-36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली-55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय-सूची

विकीलीक्स खुलासा
'वोट के बदले नोट' यूपीए सरकार पर कलंक............ 6
राजग ने प्रधानमंत्री से त्यागपत्र मांगा............ 8

विधानसभा चुनावों पर विशेष रिपोर्ट
बह रही बदलाव की बयार
&lI tho dekj flUgk............ 9

लेख
प्रधानमंत्री द्वारा असमर्थनीय घूसखोरी का बचाव
&ykyÑ".k vkMok.kh............ 12
आम आदमी की दृष्टि में आम बजट
&lR;iky............ 22
भारतीय जनता पार्टी : एक संक्षिप्त इतिहास
&Mk- f'ko 'kfDr cDlh............ 25

आम बजट 2011&12 पर चर्चा
डॉ. मुरली मनोहर जोशी............ 15
रविशंकर प्रसाद............ 18
प्रभात झा............ 21
पीयूष गोयल............ 21

राज्यों से
eè; çns'k ¼ प्रदेश कार्यसमिति बैठक............ 28
mÙkj çns'k ¼ प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो............ 30
fgekpy çns'k ¼ भाजपा-शासित राज्यों के प्रति भेदभाव............ 30

संपादक के नाम पत्र...

vknj.kh; liknd egkn;]

'कमल संदेश' पाक्षिक पत्रिका का नियमित पाठक हूं। इस पत्रिका से बहुत जानकारी मिलती है। इस पत्रिका में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सभी विषयों पर समसामायिक लेख लिखे जाते हैं। जो काफी महत्वपूर्ण होते है। वर्तमान सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया वो आम आदमी के लिहाज से आम हो ही नहीं सकता क्योंकि इस बजट में कोई बात संतोषजनक है ही नहीं जो आम आदमी को खुशी दे सके। बजट को देखें हम तो बजट ने आम आदमी को कहीं का नहीं छोड़ा। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाना एक आम आदमी के लिए काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि वस्तुओं के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। आम आदमी को दो वक्त की रोटी नसीब हो पाएगी या नहीं ये कह पाना जरा मुश्किल है। वर्तमान सरकार ने सत्ता प्राप्ति के बाद कहा था कि शीघ्र ही हम महंगाई पर काबू पा लेंगे, लेकिन महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यह महंगाई लगातार छः वर्षों से कांग्रेस के कार्यकाल के समय से बढ़ती जा रही है। आम आदमी अपना पेट तो भर ही नहीं पा रहा है वह अपने परिवार का पेट कहां से भरेगा? जब देश में भ्रष्ट नेता बैठे राज कर रहे हों तो आम जनता कहां जाए? क्या करे? किसे अपनी आप–बीती सुनाए? मैं चाहता हूं कि ये पत्रिका मेरी तरफ से इन प्रश्नों का उत्तर वर्तमान यूपीए सरकार से जरूर मांगे। मेरी इच्छा है कि कांग्रेस सरकार की जगह किसी अन्य पार्टी की सरकार आगामी वर्षों में बने। भारत की जनता को इसके बारे में बहुत ही बारीकी से सोचना होगा। मेरे विचार में भाजपा सरकार ही एकमात्र ऐसी सरकार है जो वर्तमान विकट संकट से, असहाय और भ्रमित भारतीय जनता को निकाल सकती है। और भारतीय जनता को इसकी बहुत जरूरत है।

lrh'k dekj
नई दिल्ली

व्यंग्य चित्र

हमें लिखें..

सम्पादक के नाम पत्र

कमल संदेश

सादर आमंत्रित

आपकी राय एवं विचार

सम्पादक,
कमल संदेश
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी–66
सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003
ई-मेल:
kamalsandesh@yahoo.co.in

सम्पादकीय

अनैतिक तौर पर विश्वासमत प्राप्त सरकार से नैतिकता की उम्मीद नहीं

Hkkरतीय संसद में विषयों पर बहस नहीं होने देना सत्ता पक्ष का शगल हो गया है। क्या इसे लोकतंत्र में वाजिब कहा जा सकता है? क्या सत्ता पक्ष कांग्रेस–नीत यूपीए को ऐसा करना चाहिए? आखिर! संसद में बहस नहीं होगी तो क्या होगा? कांग्रेस हर मसले पर कटघरे में है। वह बहस से भागकर अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। अवसरवादियों का गठबंधन, जहां मंत्रालय बंटता नहीं बिकता हो, ऐसे मंत्रियों और सांसदों से देश को कोई अपेक्षा बची नहीं रह गई है।

हम सभी जानते हैं कि बजट सत्र से पूर्व शीतकालीन सत्र जेपीसी की मांग में भेंट चढ़ गया। यह बजट सत्र बहस नहीं सिर्फ सत्तापक्ष की कार्रवाई और खानापूर्ति में लगा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पर हुई बहस को यूपीए टाल नहीं सकती थी, अतः जैसे–तैसे वह बहस हुई। लेकिन कटघरे में खड़ी यूपीए सरकार सांसदों के खरीद–फरोख्त मामले पर बहस नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? यह किसी की समझ में नहीं आ रहा।

आखिर, कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह संसद में गलत बयानी क्यों करते हैं? भारत के इतिहास में भारत को खैरात का प्रधानमंत्री कभी नहीं मिला। खैरात यानि डॉ. मनमोहन सिंह ने कभी नहीं सोचा था कि वे भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने इसके लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया। वे कभी लोकसभा का चुनाव नहीं जीते। वे कोई जन्म से नेता तो थे नहीं? उन्हें कभी राजनीति में मेहनत करनी नहीं पड़ी। वे तो ''राजनैतिक परिस्थितियों'' के कारण बिना बीज के उपजे व्यक्तित्व हैं। राजनेता की न उनमें साख है और न धाक। वे तो एक नौकरशाह थे और उनकी तुलना देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों से करना स्वयं की समझ के साथ मजाक ही कहा जाएगा? न व्यक्ति, न व्यक्तित्व। भाग्य का खेल। 'मजबूर' प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह स्वयं क्या सोचते हैं पता नहीं पर देश क्या सोचता है उनके बारे में इस बात को उन्हें और उनके शासन के नुमाईंदों को अवश्य सोचना चाहिए?

भारतीय संसद की गरिमा सदैव ईमानदार रही है। एक मत से पूर्व प्रधानमंत्री अटलजी की सरकार गिर गयी, पर वे कभी खरीद–फरोख्त में नहीं गए। वे लोकतंत्र की आत्मा के उपासक रहे। वे जानते थे कि विश्वासमत से प्राप्त कुर्सी ही लोकतंत्र में नैतिक बल देती है। इसलिए अगर एकमत से विश्वासमत गिर गया तो उन्होंने एक मिनट में प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया। पर आज क्या हो रहा है? अनैतिक रूप से, सांसदों की खरीद–फरोख्त कर अपनी सरकार बचाने वाले डॉ. मनमोहन सिंह की क्या स्थिति है? वे स्वयं विचार कर सकते हैं। क्या लोकतंत्र में अविश्वासमत के विरूद्ध उन्होंने जिस तरह से विश्वास मत हासिल किया, क्या उससे उन्हें बल मिला या वे नैतिक रूप से कमजोर हुए? भारत इस समय एक ऐसे प्रधानमंत्री के कार्यकाल से गुजर रहा है, जो जनता का विश्वास खो चुका है। इतना ही नहीं, वे तो सदन के एक बड़े वर्ग का भी विश्वास खो चुके हैं। अगर साख–धाक खोकर, कोई सरकार में अनैतिक रूप से बनी भी रहे तो वह नैतिक कार्य कर ही नहीं सकती। यही कारण है कि अनैतिक तौर पर विश्वास मत प्राप्त करने वाली डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार आज भारत के जन–जन का विश्वास खो चुकी है। आज अगर आम चुनाव होगा तो भारत की राजनीति में कांग्रेस उस आंकड़े पर पहुंच जाएगी जहां से उसे उबरने में वर्षों लग जायेंगे? यही कारण है कि कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार जैसे–तैसे कुर्सी बचाने में लगी हुई है। खैर कहावत है बिल्ली की मां कब तक खैर मनायेगी, आज नहीं तो कल ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा ही। ■

'वोट के बदले नोट' यूपीए सरकार पर कलंक

प्रधानमंत्री ने ''वोट के बदले नोट'' घपले पर बयान दिया है जिसमें यूपीए के समर्थन का लालच देकर अन्य राजनैतिक सदस्यों की संख्या के बल पर 22 जुलाई 2008 में विश्वास मत प्राप्त करने में सफलता पाई गई थी। सीबीआई ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने चल रहे श्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति पर अपने शपथपत्र में तब्दीली की थी। इससे समाजवादी पार्टी ने अपनी स्थिति पलट दी थी और यूपीए के समर्थन की घोषणा की थी। इसके अलावा भी विपक्षी पार्टियों के संसद के अनेक सदस्यों को लालच देने का प्रयास किया गया ताकि वे विश्वासमत में सरकार का समर्थन करें। अब यह बात निश्चित तौर पर स्थापित हो गई है कि सांसदों को घूस दी गई। सरकार को समर्थन के लिए घूस के प्रमाण इस प्रकार हैः

(क) क्रास–वोटिंग से जिन्हें प्रमुख लाभ मिलना था, वे थे प्रधानमंत्री और यूपीए सरकार।

(ख) अनेक सदस्यों की शिकायत थी कि अनेकों सदस्यों/व्यक्तियों ने सरकार के पक्ष मे वोट देने के लिए बहुत बड़ी राशि का प्रलोभन दिया था।

(ग) एक सांसद ने तीन लोकसभा सांसदों पर क्रास वोट करने के लिए उन्हें समझाने–बुझाने की कोशिश की। इस मामले की जांच करने वाली संसदीय समिति ने कहा था ''समिति अभी भी महसूस करती है कि श्री रेवती रमन सिंह जैसे प्रतिष्ठित कद के व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए.... जिससे श्री रेवती रमन सिंह बनाम अन्य प्रयासकर्ताओं का आचरण संविधान की अनुसूची के अतिक्रमण में समाजवादी पार्टी के सदस्यों की दल–बदलने के मामले में संदेह के दायरे में आ जाता है। ये घटनाएं कैमरे में कैद हो चुकी हैं।

लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज और राज्य सभा में विपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली का 'वोट के बदले नोट' घपले पर माननीय प्रधानमंत्री की सफाई पर 18 मार्च को जारी संयुक्त वक्तव्य

(घ) तत्पश्चात, जिन सांसदों को प्रभावित किया जाना था, वे एक और वरिष्ठ नेता से मिले जो सरकार के पक्ष में समर्थन इकट्ठा कर रहा था। यह भी कैमरे में कैद हो चुका है।

धनराशि को एक हस्तक्षेपकर्ता को दिया गया, जिसे यह राशि तीन सांसदों को देनी थी। इस हस्तक्षेपकर्ता का नाम संजीव सक्सेना है। जांच समिति ने कहा है ''समिति पहले ही संजीव सक्सेना द्वारा समिति के सामने रखे गए साक्ष्यों की अविश्वसनीयता पर टिप्पणी कर चुकी है... शायद श्री सक्सेना सच नहीं बोल रहे हैं कि वह अब श्री अमर सिंह की नौकरी नहीं कर रहे हैं... श्री सक्सेना जाने–अनजाने घूस प्रदाता थे। अतः उन्हें संविधान के अनुच्छेद 105 में बचाव का हक प्राप्त नहीं है... जिनकी ओर से श्री सक्सेना काम कर रहे थे... अतः इस मामले में और आगे जांच करने की आवश्यकता है। क्रासवोट का प्रस्ताव, बैठकों के तथ्य, धनराशि की सुपुर्दगी सभी कुछ कैमरे में कैद हैं। बातचीत के तथ्य टेलीफोन–कॉल रिकार्डों से सिद्ध हो जाते हैं।

संसदीय समिति 4 के मुकाबले 3 सदस्यों में विभाजित थी। यहां तक कि घूस प्रदाता की भूमिका पर भी बहुमत का यही मत है और माना है कि उपर्युक्त मामलों में और आगे जांच की आवश्यकता है। सात सदस्यों में से जिन 3 लोगों की विसम्मति है, उससे यह पूरी तरह से घूस प्रदाताओं की भूमिका सिद्ध हो जाती है।

विकीलीक्स के नवीनतम पर्दाफाश से तीन नए साक्ष्य सामने आए हैं:

1. अमेरीकी डिप्लोमेट नोटों के ढेर जमा करने का गवाह है जिसे रिश्वत देने के लिए उपयोग किया जाना था।
2. वह उन षड्यंत्रकारियों को पहचान सकता है, जो रिश्वत लेने में शामिल थे।
3. षड्यंत्रकारियों ने उस (डिप्लोमेट) के सामने माना था कि वे सांसद क्रासवोट के लिए रिश्वत लेने के अपराधी हैं।

अतः भारतीय पार्टी प्रधानमंत्री से सफाई की मांग करती है कि–

1. आप विश्वासमत की सफलता के प्रमुख लाभकर्ता थे। निश्चित ही रिश्वत देने का मामला बनता है।

शेष पृष्ठ 8 पर

विकीलीक्स के खुलासे पर संसद में विपक्ष ने की सरकार की जबरदस्त घेरेबंदी

&laoknnkrk }kjk

प्रधानमंत्री इस्तीफा दें : लालकृष्ण आडवाणी

विकीलीक्स के खुलासों को एनडीए के तीन साल पुराने आरोपों की पुष्टि करार देते हुए विपक्ष ने 17 मार्च को प्रधानमंत्री के फौरन इस्तीफे की मांग कर डाली। एनडीए के कार्यकारी अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने संसद परिसर में खचाखच भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन खुलासों से अब इस बात में कोई शक नहीं कि 2008 में सरकार बचाने के लिए कमजोर सांसदों को ढूंढ़कर उन्हें पैसे देने की मुहिम चलाई गईए जो कि भाजपा के कुछ सांसदों ने 'कैश फॉर वोट' के जरिए उजागर भी किया। श्री आडवाणी का कहना था कि इन खुलासों के बाद मनमोहन सिंह शासन का नैतिक अधिकार खो चुके हैं और उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा व उसके सहयोगी चाहे इसी क्षण चुनाव के लिए तैयार हों मगर हो सकता है अन्य विपक्षी दलों के कई ऐसे सांसद होंगे, जो इतनी जल्दी चुनाव मैदान में न जाना चाहें। श्री आडवाणी ने राज्यसभा में दिए गए प्रणब मुखर्जी के बयान को भी सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि मुखर्जी की दलील पर उन्हें हैरानी होती है कि चौदहवीं लोकसभा के भंग हो जाने से यह मामला प्रासंगिक नहीं रहा। श्री आडवाणी ने दावा किया कि नए खुलासे से भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ महीनों से जारी भाजपा की मुहिम को और ताकत मिलेगी।

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति के गठन के बाद अभी सरकार ने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि विकीलीक्स के खुलासे ने एक बार फिर उसे कठघरे में खड़ा कर दिया। विकीलीक्स खुलासे के मुताबिक 2008 में भारत–अमेरिका परमाणु करार पर सदन का विश्वास मत हासिल करने के लिए सांसदों की खरीद–फरोख्त हुई। विपक्ष ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग की है।

लोकसभा में यह मुद्दा उठाते हुए विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि विकीलीक्स द्वारा किए जा रहे चौंकाने वाले खुलासे दुनिया में भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार करते हैं। यह खुलासा एक तथाकथित ईमानदार प्रधानमंत्री के तहत भ्रष्टाचार को सामने लाता है।

उन्होंने कहा कि यह सरकार शासन करने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। प्रधानमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे तीन सांसद उस समय संसद में नोटों का बंडल लेकर आए थे और कहा था कि पैसे लेकर विश्वासमत हासिल किया जा रहा है। उनकी बात सुनने की बजाय उन्हें ही दोषी करार दिया गया। कहा गया कि सदन में नोट लहराना अपराध है। धन देकर वोट हासिल करना अपराध नहीं है लेकिन नोट लहराना अपराध है।

श्रीमती स्वराज ने कहा कि इस खुलासे में मंत्रियों के नाम हैं, उनके करीबियोंए नेताओं और उनके सहयोगियों के नाम हैं। जो लोग ऐसा कार्य कर रहे थे, यह सरकार उन्हें पद्म भूषण देती है।

राज्यसभा में शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने कहा कि विकीलीक्स के खुलासे से साबित हो गया है कि सरकार राजनीतिक और नैतिक अपराध के आधार पर बची है। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार को एक मिनट भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है जो इस तरह के राजनीतिक अपराध के आधार पर बची है। हम मांग करते हैं कि इस सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए।

श्री जेटली ने कहा कि विकीलीक्स का हालिया खुलासा बताता है कि उस समय कैसी दबाव की स्थिति थी और हमारे लोकतंत्र का किस तरह अपमान किया गया। उन्होंने कहा कि उस समय वर्ष 2008 में जो आशंका जताई जा रही थी वह विकीलीक्स के खुलासे से सच साबित हो गई है। उस समय सरकार अल्पमत में थी और विश्वास मत हासिल करने के लिए किस तरह धन का इस्तेमाल किया जा रहा था, यह बात अमेरिकी अधिकारियों के साथ तत्कालीन बातचीत से जाहिर हो गई है।

विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने अंग्रेजी दैनिक हिन्दू में प्रकाशित खबर के हवाले से कहा कि संप्रग ▸▸

▸▸ सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान भारत अमेरिका परमाणु करार को लेकर वाम दलों के समर्थन वापस लेने के बाद विश्वास मत हासिल करने के लिए सांसदों को धन दिया गया था। उन्होंने कहा कि उस समय सरकार के पास बहुत ही मामूली बहुमत था। जेटली ने कहा कि विश्वास मत हासिल करने के लिए जिन लोगों को धन दिया गया, उनके नाम भी सामने आए हैं। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए।

कांग्रेस सदस्यों के इस पर विरोध जताने पर श्री जेटली ने कहा कि क्या तथ्य इतने शर्मिन्दा करने वाले हैं कि सत्तारूढ़ दल सदन में व्यवधान डाल रहा है। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल साफ है कि यह सरकार राजनीतिक अपराध की वजह से बच पाई है। इस पर विपक्षी सदस्यों ने 'शर्म करो' के नारे लगाए। श्री जेटली ने कहा कि ऐसे नैतिक अपराध से बची सरकार को सत्ता पर बने रहने का कोई हक नहीं है और उसे तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ■

पृष्ठ 6 का शेष

यहां तक संसदीय जांच के बहुमत सदस्यों ने भी माना है कि श्री सक्सेना घूसप्रदाता थे। आपने या आपकी सरकार ने यह मामला जांच के लिए सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा? आपने सच की जांच को छुपाने और दोषियों को दण्ड देने का प्रयास क्यों किया? क्या आप अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही के दोषी नहीं हैं? क्या आप लोकसभा की संसदीय समिति की सिफारिशों का अनुपालन न करने पर संसद के विशेषाधिकारों का भंग नहीं कर रहे हैं?

2. संसदीय समिति की जांच के सांसदों द्वारा दी जा रही घूस के निष्कर्षों को देखते हुए आप ने 'इंण्डिया टूडे कंक्लेव' में कैसे कह दिया कि आप घूस दिए जाने के तथ्यों से अवगत नहीं थे?
3. क्या आपने इस घटना के कुछ हतों बाद न्यूज चैनलों पर प्रसारित घूस देने सम्बंधी अदायगी की वीडियो रिकार्डिंग देखने का मौका नहीं मिला?
4. क्या कभी आपकी अंतरात्मा पर यह बोझ नहीं पड़ा कि आपको ऐसे संदिग्ध साधनों का प्रयोग कर विश्वासमत प्राप्त किया जिससे घर और बाहर भारत की छवि धूल में मिल गई?
5. आज बहुत देर हो जाने पर भी क्या आपको जरा भी पश्चाताप है और क्या आप इतनी भारी गलती को स्वीकार करने की जिम्मेदारी लेते हैं और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार है? ■

राजग ने प्रधानमंत्री से त्यागपत्र मांगा

'वोट के बदले नोट' मामले पर विकीलीक्स खुलासे पर राजग द्वारा 17 मार्च 2011 को जारी प्रेस विज्ञप्ति

जुलाई 2008 में राजग ने कहा था, संप्रग–1 ने रिश्वत के प्रभाव से विश्वासमत को अपने पक्ष में कर लिया था। विकीलीक्स केबल जो सामने आया है वह एक अमरीकी राजनयिक द्वारा अपने सरकार को भेजी गई सूचना है। यह 2008 की घटना से संबंधित है। वह राजनयिक अमरीकी दूतावास में सलाहकार के पद पर कार्यरत थे अमरीकी तभी विश्वासमत में रुचि रख रहे थे। कानून का उल्लंघन करने वालों में से एक पूरी तरह से कांग्रेस के विदेश प्रकोष्ठ में कार्यरत था। अहंकार से भरी कांग्रेस ने इस राजनयिक को नोटों से भरा बक्सा दिखाया। यह राजनयिक निश्चित ही अपने केबल में तथ्य को तोड़–मरोड़ नहीं रहा होगा। संत चटवाल जैसे लोग अकाली दल को लुभाने के लिए लगाए गये। हालांकि वे सफल नहीं हुए परन्तु अपने प्रयासों के लिए सरकार से पुरस्कृत किए गए। यह तथ्य अब सरकार की राजनैतिक नैतिकता पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं। संप्रग–1 इस राजनीतिक पाप के कारण ही बच पाई। प्रधानमंत्री को इस सरकार का नेतृत्व करने का प्रधानमंत्री को कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। उन्हें तुरन्त त्यागपत्र देना चाहिए।

राज्यसभा में वित्तमंत्री का यह कहना कि राजनयिक मर्यादाएं उन्हें केबल की जांच करने से रोकती है, को सही नहीं कहा जा सकता। राजनयिक मर्यादा केबल की गोपनीयता पर लागू होती है। परन्तु केबल आमजन तक पहुंच चुका है। राजनयिक मर्यादा एक भारतीय को कानून का उल्लंघन करने का भी अधिकार नहीं देती। वह भी जबकि उसने भारत में रिश्वत देने का अपराध किया हो। श्री प्रणव मुखर्जी का यह कहना कि कानून का उल्लंघन का मामला 14वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही खत्म हो गया, सही नहीं है क्योंकि रिश्वत का अपराध संसद के बाहर किया गया था अतः 14वीं लोकसभा के भंग होने के साथ अपराध खत्म नहीं होता। ये खुलासे राजग के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को बल देती है। ये भ्रष्टाचार के आरोप इस सरकार पर, जब तक सत्ता में है, प्रश्न खड़े करते रहेंगे।

राजग मांग करती है कि इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, अतः उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। ■

बह रही बदलाव की बयार

&l:tho dekj flUgk

देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। इन पांच राज्यों में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी शामिल हैं। प. बंगाल में चुनाव 6 चरणों में और असम में 2 चरणों में होंगे। तमिलनाडू, केरल और पुडुचेरी में चुनाव एक ही चरण में होंगे। वोटों की गिनती 13 मई को की जाएगी।

आसन्न विधानसभा चुनाव देश में वामपंथी राजनीति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल व केरल में वामपंथी दलों का शासन है इसलिए उनके लिए इस बार जीवन–मरण का प्रश्न है। पश्चिम बंगाल में साढ़े तीन दशकों से शासन कर रहे वामपंथी गठबंधन को विपक्षी दलों से अब तक की सबसे कड़ी चुनौती मिल रही है। असम और पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार है तो तमिलनाडु में द्रमुक का शासन है।

सिल्चर (असम) में आयोजित चुनावी जनसभा के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी

असम चुनाव में अभियान में जुटी श्रीमती हेमा मालिनी

पांचों राज्यों में राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सत्तारूढ़ दल जहां अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का हवाला देते हुए चुनाव प्रचार को गति प्रदान कर रहे हैं तो वहीं विपक्षी दल भ्रष्टाचार, महंगाई और स्थानीय समस्याओं का मसला जोर–शोर से उठा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में छह चरणों (पहला चरण– 18 अप्रैल, दूसरा चरण– 23 अप्रैल, तीसरा चरण– 2 अप्रैल, चौथा चरण–3 मई, पांचवा चरण– 7 मई, छठा चरण–10 मई) में चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य इस बार साफ नज़र आ रहा है। वाममोर्चा को इस बार कड़ी चुनौती मिल रही है। यहां वामपन्थी दलों को पहले लोकसभा चुनावों में और उसके बाद नगर निगम चुनावों में मुंह की खानी पड़ी थी। इस बार कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद दोनों दलों में सीटों का बंटवारा हो सका। इस समझौते के तहत कांग्रेस 65 सीटों पर तथा तृणमूल कांग्रेस 229 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ छोटी पार्टियों के साथ मिलकर प्रदेश की सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि वह पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि अगर उनकी पार्टी जीती तो वह सरकार की अगुवाई करेंगी और छह महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव जीत लेंगी। विपक्षी दल नक्सली हिंसा, सरकारी संरक्षण में आतंक, माकपा द्वारा मतदाता सूची में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी करना, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे अहम समस्याओं को मुद्दा बनाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं वाममोर्चा के पास सफलताएं गिनाने के लिए कुछ

खास है नहीं इसलिए वह यूपीए सरकार की असफलताओं को मुद्दा बनाकर जनता के बीच जा रहा है।

nyxr fLFkfr

ny	lhV
वाममोर्चा (माकपा–175)	233
कांग्रेस+	24
तृणमूल कांग्रेस	30
अन्य	6
dy lhV	293

केरल

केरल में 13 अप्रैल को होने जा रहे राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी जोरों पर है। राज्य में मुख्य रूप से सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और विपक्षी कांग्रेस नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के बीच मुकाबला है। यहां पिछले कुछ समय से हर बार सरकार बदलने की परम्परा चली आ रही है। लेकिन केरल में कांग्रेस की राह इतनी आसान भी नहीं है जितनी नज़र आ रही है क्योंकि वामदलों और भाजपा ने यहां पीजे थॉमस मुद्दे पर सरकार को घेरने की व्यापक रणनीति बनाई है। भाजपा इस बार जोर–शोर से चुनाव लड़ रही है। गौरतलब है कि गत पंचायत, नगर निगम और नगरपालिका चुनावों में भाजपा अपनी उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। यहां भी वाम दलों की सरकार के प्रति लोगों में आक्रोश व्याप्त है। माकपा के दो बड़े नेताओं बी एस अच्युतानंदन व राज्य माकपा के सचिव एम विजयन के बीच लगातार जारी संघर्ष ने राज्य में पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पिछले दिनों माकपा ने अब्दुल नासिर मदनी की पार्टी पीडीपी से गठबंधन किया था, इसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। केरल में विकास, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, कानून एवं व्यवस्था, पेयजल की समस्या आदि राजनीतिक मुद्दा बना है, जिसके आधार पर चुनाव लड़े जा रहे हैं।

nyxr fLFkfr

ny	lhV
एलडीएफ (माकपा+)	98
यूडीएफ (कांग्रेस+)	42
dy lhV	140

असम

असम में 2 चरणों (पहला चरण–4 अप्रैल और दूसरा चरण–11 अप्रैल) में विधानसभा चुनाव के मतदान होने हैं। 126 सदस्यीय विधानसभा में त्रिकोणीय– सत्तारूढ़ कांग्रेस, भाजपा और असम गण परिषद के बीच मुकाबला है। यहां भी भारतीय जनता पार्टी सभी 126 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सबसे ज्यादा उम्मीद असम से ही है। पिछली बार पार्टी के दस विधायक जीते थे। इसलिए सरकार गठन में भाजपा की प्रभावी भूमिका रहेगी। राज्य में आतंकवाद, वोट बैंक की राजनीति, अवैध घुसपैठ और भ्रष्टाचार चुनावी मुद्दा है।

nyxr fLFkfr

dkx lhV	53
अगप+	28
भाजपा	10
अन्य	35
dy lhV	126

तमिलनाडू

तमिलनाडु में 13 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां दो क्षेत्रीय दलों द्रमुक व अन्नाद्रमुक के गठबंधन तथा भाजपा के बीच संघर्ष है। कांग्रेस यहां द्रमुक की सहयोगी पार्टी के रूप में 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस चुनाव में भ्रष्टाचार अहम मसला है। श्रीलंका में तमिल समस्या भी मुद्दा बन रहा है। 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा की संलिप्तता के चलते द्रमुक को नुकसान उठाना पड़ सकता है। चूंकि राज्य में तीसरी शक्ति मजबूत स्थिति में नहीं है इसलिए मतदाताओं को करुणानिधि या जयललिता में से ही किसी का चुनाव करना पड़ेगा। दोनों पर ही भ्रष्टाचार के आरोप हैं।

nyxr fLFkfr

Mh,ed$	163
(डीएमके–96, कांग्रेस–34)	
एआईएडीएमके+	69
(एआईएडीएमके–61, एमडीएमके–6)	
अन्य	2
dy lhV	234

पुडुचेरी

पुडुचेरी में 13 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां कांग्रेस की सत्ता है। राज्य की राजनीति कमोबेश तमिलनाडु के साथ ही चलती है। इस केंद्र शासित प्रदेश में द्रमुक, अन्नाद्रमुक और भाजपा के बीच ही मुकाबला होगा।

nyxr fLFkfr

Mhih,	20
एआईएडीएमके	7
अन्य	3
dy lhV	30

आसन्न पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। पांच राज्यों में से दो राज्यों–पश्चिम बंगाल और केरल में वामपंथी दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तीन राज्यों में यूपीए के घटक की सरकार होने के चलते सबसे ज्यादा यूपीए को ही नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि केन्द्र में हुए राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श आवास घोटाला, सीवीसी पद पर पीजे थॉमस की नियुक्ति का मामला, इसरो घोटाला तथा बेलगाम महंगाई से मतदाताओं में जबर्दस्त आक्रोश है। ■

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री त्यागपत्र दें : गडकरी

&gekj% l~oknnkrk }kjk

Xत 14 मार्च 2011 को मुंबई के आजाद मैदान में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने मांग की कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण को सीवीसी नियुक्ति मामले में त्यागपत्र दे देना चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों से आह्वान किया कि उन्हें माफियाओं से राज्य को मुक्ति दिलानी चाहिए।

श्री गडकरी का यह भी कहना था कि प्रधानमंत्री कार्यालय में तत्कालीन राज्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के पास पीजे थॉमस की पामोलीन घूस मामले की संलिप्तता संबंधी तथाकथित गोपनीय कागज़ात थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री और चयन समिति के सामने इन सभी तथ्यों को क्यों नहीं रखा?

श्री गडकरी ने आगे कहा कि हालांकि केरल सरकार ने केन्द्र के पास पामोलीन घूस मामले संबंधी थॉमस के कागज़ात भेज दिए थे तो सीवीसी चयन समिति के तैयार की गई फाइल में थॉमस के खिलाफ लंबित आरोपों का तत्कालीन पीएमओ में राज्यमंत्री होने के नाते जिक्र क्यों नहीं किया गया? स्पष्ट है कि चव्हाण ने सीवीसी की महत्वपूर्ण सूचना प्रधानमंत्री और सीवीसी चयन समिति से छुपाकर इस नियुक्ति में पूर्णतः भ्रमित किया है।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सीवीसी के रूप में एक दाग़ी ब्यूरोक्रेट की नियुक्ति के लिए वे पूर्णतः जिम्मेवार हैं, अतः उन्हें अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और तुरंत ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए।

प्रधानमंत्री द्वारा राज्यसभा में हाल में दिए गए एक बयान की आलोचना करते हुए, जिसमें कहा गया था कि पृथ्वीराज चव्हाण थॉमस के खिलाफ लंबित आरोपों की सूचना नहीं दी, श्री गडकरी ने तत्कालीन पीएमओ में राज्यमंत्री पर प्रधानमंत्री और सीवीसी चयन समिति को गुमराह करने का आरोप लगाया जबकि सच तो यह है कि केरल सरकार ने केन्द्र सरकार के पास पामोलीन घूस मामले में थॉमस संबंधित पत्रों को पृथ्वीराज चव्हाण को भेज दिया था।

उन्होंने आगे कहा कि यह तो चव्हाण ही जानते होंगे कि उन्होंने प्रधानमंत्री से इन काग़जात को क्यों छिपाया? अब हमारे पास केरल सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजे गए संबंधित पत्रों की प्रतियां हैं जिसमें मार्च 2008 में थॉमस को 1991 में पाम ऑयल आयात मामले की लंबित जांच के कारण उन्हें केन्द्र में नियुक्ति पर आपत्ति जतायी थी।

महाराष्ट्र में कांग्रेस –एनसीपी गठबंधन सरकार की भर्त्सना करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना था कि राज्य में माफिया राज है। यहां कोई कानून –व्यवस्था नहीं है, महंगाई पराकाष्ठा पर है और आम आदमी की बात कोई सुनने वाला नहीं है। इस

अवसर पर श्री गडकरी ने विशाल जनसमूह से ' माफिया हटाओ महाराष्ट्र बचाओ' का नारा देकर राज्य में फैले माफिया राज को समाप्त करने का आह्वान किया और कहा कि इस निकम्मी सरकार के विरूद्ध लोग जाग्रत हों।

लोकसभा में भाजपा के उपनेता श्री गोपीनाथ मुण्डे ने भी इस अवसर पर राज्यसभा में एनसीपी के गृहमंत्री आर आर पाटिल की आलोचना की कि उन्होंने 2 जनवरी को नासिक जिले के एडीशनल कलक्टर यशवंत सोनवाणे को जिंदा जलाने में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया।

भाजपा अध्यक्ष श्री सुधीर मुंगतीवर, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता, श्री एम नाथ खॉडसे तथा कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार की हर दिशा में विफलता के कारण सरकार की भर्त्सना की। ■

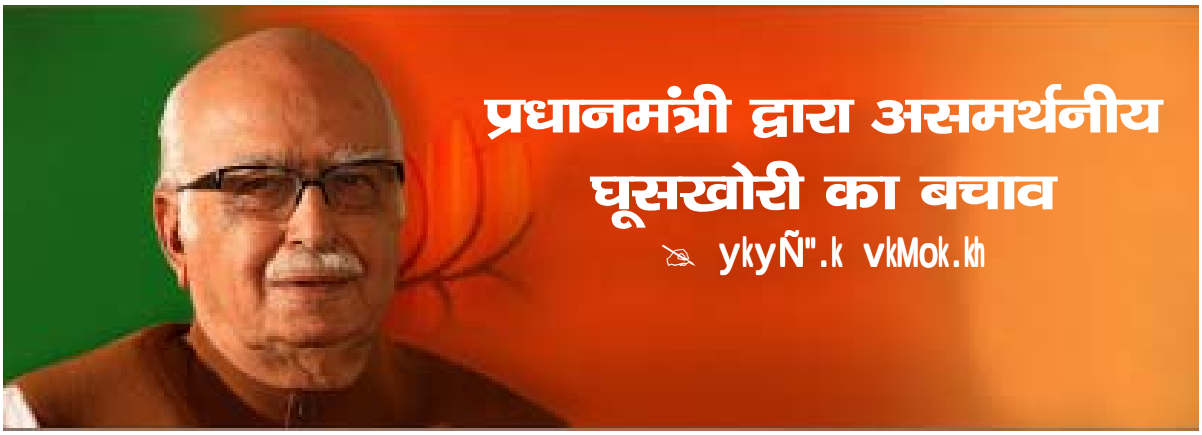

प्रधानमंत्री द्वारा असमर्थनीय घूसखोरी का बचाव

✍ ykyÑ".k vkMok.kh

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 18 मार्च, 2011 को संसद के दोनों सदनों में एक वक्तव्य देकर स्वतंत्र भारत में अब तक के सबसे बड़े घोटाले–जुलाई 2008 में नोट के बदले वोट पर पर्दा डालने के उद्देश्य से उन्मत्त परन्तु व्यर्थ प्रयास किया। वक्तव्य के तुरंत पश्चात् दोनों सदनों में विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने अपने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में इस वक्तव्य के प्रत्येक पहलू की प्रभावी ढंग से हवा निकाल दी और प्रधानमंत्री से निम्नलिखित पांच प्रश्न पूछे जिनका उत्तर पूरा देश चाहता है:

1. विश्वास मत के मुख्य लाभार्थी आप हैं। सभी ने स्वीकारा है कि यह घूसखोरी का केस है। यहां तक कि संसदीय जांच में अधिकांश ने श्री सक्सेना को घूस देने वाला माना है। क्यों नहीं आपने या आपकी सरकार ने इस मामले को सीबीआई को जांच हेतु सौंपा? क्यों आपने सत्य की जांच को छुपाने और दोषियों को दण्डित न करने की कोशिश की? क्या आप अपने कर्तव्य पालन न करने के दोषी हैं? लोकसभा की संसदीय समिति की सिफारिशों को लागू न करने के चलते क्या आप संसद की अवमानना के दोषी नहीं हैं?
2. संसदीय जांच में यह पाए जाने के बावजूद कि सांसदों को घूस दी गई, क्यों आपने इंडिया टूडे कान्क्लेव को बताया कि घूसखोरी के बारे में आपको कुछ नहीं पता है?
3. क्या आपको घूस देने की वीडियो रिकार्डिंग्स को देखने का मौका मिला जो कुछ सप्ताह बाद समाचार चैनलों पर दिखाई गईं?
4. क्या कभी आपकी अंतरात्मा ने आपको नहीं कचोटा कि जिन संदिग्ध तरीकों से आपने विश्वास मत हासिल किया, उनसे देश और विदेशों में भारत की छवि कलंकित हुई?
5. देर से क्यों न सही, क्या आप अभी भी ऐसी भयंकर भूल की जिम्मेदारी स्वीकार कर प्रधानमंत्री के रुप में अपना त्यागपत्र देकर प्रायश्चित करने को तैयार हैं?

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 18 मार्च, 2011 को संसद के दोनों सदनों में एक वक्तव्य देकर स्वतंत्र भारत में अब तक के सबसे बड़े घोटाले–जुलाई 2008 में नोट के बदले वोट पर पर्दा डालने के उद्देश्य से उन्मत्त परन्तु व्यर्थ प्रयास किया।

हालांकि, मनमोहन सिंह द्वारा अपने वक्तव्य में प्रतिपादित बेतुके सिद्धांत की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करके मैं चाहूंगा कि कांग्रेससजन उनसे यह सवाल पूछें।

14वीं लोकसभा द्वारा घूसखोरी के आरोपों की जांच करने हेतु गठित समिति का उल्लेख करने के बाद प्रधानमंत्री कहते हैं:

"मैं इससे निराश हूं कि विपक्ष के सदस्य उसके पश्चात् क्या हुआ उसे भूल गए। 14वीं लोकसभा की अवधि पूरी होने पर आम चुनाव हुए। उन आम चुनावों में विपक्षी दलों ने बार–बार विश्वास मत में घूसखोरी के आरोपों को दोहराया था। लोगों ने इन आरोपों का क्या जवाब दिया? 14वीं लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल जिसके पास 138 सीटें थीं वह 15वीं लोकसभा में घटकर 116 सीटों पर आ गया। वाम दलों की संख्या भी 59 से 24 हो गई। अकेले कांग्रेस पार्टी ही ऐसी निकली जिसकी संख्या 145 से 206 हो गई, यानी 61 सीटों की बढ़ोतरी।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष उन पुराने आरोपों को उठा रहा है जिन पर बहस हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है और

भारत की जनता ने जिन्हें नकार दिया है।" यह कब से हुआ कि चुनावी विजय को, चुनाव पूर्व किए गए अपराधों की माफी के रुप में माना जाए? क्या प्रधानमंत्री को इस भौंडे तर्क के गंभीर आयाम मालूम है?

सभी राजनीतिक विश्लेषक इसे स्वीकार करेंगे कि 1989 के लोकसभाई चुनावों जिसमें राजीव गांधी को विश्वनाथ प्रताप सिंह के हाथों परास्त होना पड़ा था, का मुख्य मुद्दा बोफोर्स तोप घोटाला था। और कोई भी यह नहीं भूल सकता कि राजीव गांधी जो 1984 में सभी रिकार्ड तोड़कर लोकसभा में 415 सीटों पर विजयी हुए थे, 1989 में 197 सीटों पर सिमट कर रह गए, जोकि आधे से भी कम होती हैं!

डा. मनमोहन सिंह द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत कि भारत की जनता ने उनके निर्लज्ज घूसखोरी प्रपंच को स्वीकृति दे दी, तो क्या उन्हें पता है कि इसी तर्क पर 1989 के लोकसभाई जनादेश का अर्थ यह निकाला जाएगा कि भारतीय मतदाताओं ने राजीव गांधी को बोफोर्स घोटाले में दोषी घोषित कर दिया ?

निर्लज्जता की कोई सीमा नहीं

एक ही सप्ताह में, हिन्दू ने विकीलीक्स के आधार पर दो समाचार रिपोटें प्रकाशित की हैं जिसमें राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की स्थिति बुरी तरह से प्रभावित हुई है।

15 मार्च, 2011 को हिन्दू में प्रकाशित पहली रिपोर्ट कहती है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम. के. नारायणन से अगस्त, 2009 में बातचीत के बाद अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोइमर ने निष्कर्ष निकाला कि डा. एम.एस. सिंह पाकिस्तान से बातचीत और वार्ता के मामले में अपने दृढ़ विश्वास के चलते अपनी सरकार के भीतर ही अलग–थलग थे, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी उनसे सहमत नहीं थे।

मैं मानता हूं कि आतंकवाद, पाकिस्तान और जम्मू–कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर यदि भारतीय जनमत का मूल्यांकन किया जाए तो डा. मनमोहन सिंह न केवल अपनी सरकार अपितु जनता में भी अपने को अलग–थलग खड़ा पाएंगे। लेकिन उनकी सरकार की छवि और यहां तक कि वैधता पर वास्तव में हथौड़े की जो मार पड़ी है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, वह हिन्दू में प्रकाशित दूसरी रिपोर्ट है जो दो दिन बाद यानी 17 मार्च, 2011 को प्रकाशित हुई है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इस रिपोर्ट को अनेक समाचार पत्रों ने यू.पी.ए. की लिए विकीबोम्ब माना है।

मैं मानता हूं कि आतंकवाद, पाकिस्तान और जम्मू–कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर यदि भारतीय जनमत का मूल्यांकन किया जाए तो डा. मनमोहन सिंह न केवल अपनी सरकार अपितु जनता में भी अपने को अलग–थलग खड़ा पाएंगे।

समाचारपत्र को यह रिपोर्ट विकीलीक्स के हवाले से मिली है। इस समाचार को हिन्दू के प्रमुख राजनीतिक सम्पादक सिद्धार्थ वर्दाराजन ने लिखा है। रिपोर्ट के मुख्य पहलू यह हैं रू

1. यह अमेरिका के चार्ज डी अफेयर्स स्टीवन व्हाईट ने वाशिंगटन को केबल भेजा है।

2. इस केबल में, व्हाईट दूतावास के राजनीतिक कांउसलर की राज्यसभा सदस्य सतीश शर्मा जोकि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के घनिष्ठ सहयोगी और सोनिया गांधी के निकट पारिवारिक मित्र के रुप में जाने जाते हैं, से मुलाकात के बारे में लिखते हैं।

वर्दाराजन के अनुसार, श्री सतीश शर्मा ने अमेरिकी राजनायिक को बताया कि वह और पार्टी में अन्य लोग 22 जुलाई के विश्वास मत में सरकार की जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल में सदस्यों पर डोरे डाले जाने का वर्णन करते हुए व्हाईट ने रहस्योद्घाटन के रुप में एक विस्फोट किया रू

"शर्मा के राजनीतिक सहयोगी नचिकेता कपूर ने दूतावास के कर्मचारी को बताया कि 16 जुलाई को अजीत सिंह के राष्ट्रीय लोकदल को 10 करोड़ रुपए (2.5 मिलियन अमेरिकी डालर) उनके चार सदस्यों को सरकार का समर्थन करने के लिए दिए गए। कपूर ने उल्लेख किया कि पैसा कोई मुद्दा नहीं है लेकिन अहम यह कि जिन्होंने पैसा लिया है वे सरकार के पक्ष में वोट डालें।"

1. ने दूतावास के अधिकारी को लगभग 50–60 करोड़ रुपए (करीब 25 मिलियन डॉलर) से भरे दो बैग दिखाए जो घर में देने के लिए रखे थे।"

2. पार्टी के अन्य भीतरी व्यक्ति ने राजनीतिक काउंसलर को बताया कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री कमलनाथ भी इस काम में सहायता कर रहे हैं। इस वार्ताकार के मुताबिक, "पहले, वह घूस के रुप में छोटे जहाज देने की पेशकश कर रहे थे। अब वह वोटों लिए जेट के लिए भी तैयार हैं।"

वर्दाराजन लिखते हैरू "यह तथ्य कि कांग्रेसी राजनीतिज्ञ विश्वासमत के सिलसिले में अपने घूसखोरी अभियान के बारे में अमेरिकी राजनयिकों से खुलकर बात कर सकते हैं– और यह कि दूसरे भी लोकतंत्र के विध्वंस में

इतने अलिप्त–यह सभी षड़यंत्रकारी हैं लेकिन अंततः दोनों सरकारों के बीच क्षमाकारी रणनीतिक भागीदारी को प्रदर्शित करता है जिसे बनाने के प्रयास हो रहे हैं।"

वर्दाराजन की इस तीखी टिप्पणी ने मुझे मेरे विशिष्ट सहयोगी जसवंत सिंह के शानदार भाषण का स्मरण करा दिया जो उन्होंने लोक सभा में गत् सप्ताह विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बहस की शुरूआत करते हुए दिया।

भारत सरकार की पाकिस्तान नीति का उल्लेख करते हुए जसवंत सिंह ने कहा:

"चाहे पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, हमारी नीति अब हमारी नहीं रहीं। मान लिया गया है कि पाकिस्तान अमेरिकी नीति के लिए अनिवार्य है। यहां तक कि आपको बहस नहीं करनी है। मुझे अच्छी तरह से स्मरण है, श्रीमान। मैं साऊथ ब्लॉक (विदेश मंत्रालय) से निकल कर नार्थ ब्लॉक (वित्त मंत्रालय) में जा चुका था। वहां एक व्यक्ति मुलाकात के लिए आए। मैं नहीं जानता कि मुझे उसका नाम लेना चाहिए या नहीं। वह एक अमेरिकी अधिकारी था। हृष्ट–पुष्ट शरीर वाला। वह मुझे वित्त मंत्रालाय में मिलने आया। तब मैंने उसे बताया कि मैं उनसे गुस्सा नहीं हूं। लेकिन आपने (हमें) गलत समझा। यदि भारत की नीति प्रबन्ध में मुझे कुछ करना होगा तो मैं कभी भी अमेरिका से पाकिस्तान के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं पूछुंगा। यह रिकार्ड पर है। श्रीमान, यह गर्वोक्ति नहीं थी। तब मैं भारत का एक प्रतिनिधि था। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अमेरिका के सहारे मत रहिए क्योंकि हम अपने उत्तर आप ढूंढ लेंगे। लेकिन यदि आप अमेरिका के माध्यम से उत्तर पाने का प्रयास करोगे या उत्तर पाओगे तो हम कभी भी उत्तर नहीं पा सकेंगे।" ■

भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा

भाजपा केन्द्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ ने केन्द्र में कांग्रेस–नीत यूपीए की सहकारी–विरोधी नीतियों पर 7 मार्च 2011 को नई दिल्ली में भारत की माननीय राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा।

केन्द्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ ने प्रस्तावित बहु–राज्यीय सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2011 पर अपनी आपत्ति उठाते हुए कहा कि यह विधेयक इस समय संसद की स्थायी समिति के पास है। प्रस्तावित संशोधन विधेयक का उद्देश्य बहु–राज्य सहकारी सोसाइटियों को नियमित करने का है अर्थात् ऐसी सोसाइटियां, जो एक से अधिक राज्यों में सदस्यों के हितों को देखता है, परन्तु इस विधेयक से उनकी स्वायत्तता कम हो जाएगी। सरकार इस संशोधित विधेयक के रजिस्ट्रार को नियुक्त करेगी, जिसके पास रेगुलेटरों के लिए असीमित शक्तियां रहेंगी और इस प्रकार देश के सहकारी आंदोलन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

प्रतिनिधिमण्डल ने कहा कि इससे सहकारी समितियों के रोजमर्रा के कामकाज में रेगुलेटरों का न केवल अनावश्यक दखल ही बढ़ेगा, बल्कि उनका सामान्य कामकाज और स्वायत्तता भी प्रभावित होगी।

ज्ञापन में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार द्वारा शुरू किए नवीन सुधारात्मक उपायों की रूपरेखा दी, जो बहु–राज्यीय सहकारी सोसाइटीज विधेयक 2002 में थीं, यह वर्तमान रूप में जैसा विधेयक है वह तो 2002 के मूल विधेयक की भावनाओं और मूल विचारों से भिन्न है, इसलिए इसका विरोध करना आवश्यक है। केन्द्रीय सहकारी प्रकोष्ठ ने भारत की राष्ट्रपति से अपील की कि वे प्रस्तावित संशोधन विधेयक से होने वाली क्षति पर कार्रवाई करें जिससे सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता कम होने तथा इन भयानक विनियमों से बचा न सकें। ■

आम बजट 2011–12 पर चर्चा

आम आदमी को राहत नहीं : डॉ. मुरली मनोहर जोशी

गत 28 फरवरी 2011 को केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने देश का 80वां आम बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया। 8 मार्च को लोकसभा में बजट पर हुयी चर्चा का आरंभ भाजपा के वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने की। डॉ. जोशी ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि विकास का जो मॉडल वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी ने इस बजट में पेश किया है, उसे आम आदमी कभी स्वीकार नहीं करेगा। हम यहां डॉ. जोशी के भाषण का सारांश प्रकाशित कर रहे हैं:–

यह सही कहना है कि बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं। बजट में उन नीतियों का और उन सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन का दिशा संकेत होता है जिस तरफ कदम बढ़ने चाहिएं। न तो पिछले साल इस सिद्धांत का पालन हुआ और न इस साल, इस सिद्धांत का पालन हो रहा है। अब हमें यह देखना है कि वर्ष 2011–12 का बजट क्या कहता है, किधर जाता है और यह किसके लिए बना है? वित्तीय प्रबंधन, फिस्कल मैनेजमेंट, ग्रोथ, विकास, इनफ्लेशन पर नियंत्रण, महंगाई पर नियंत्रण, कृषि का क्षेत्र, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट और भ्रष्टाचार का उन्मूलन। इन पांचों बातों पर यदि हम इस बजट को कसें तो बड़ी निराशा होगी। वित्त मंत्री जी ने कहा था कि राजकोषीय घाटा पिछले साल के 5.5 प्रतिशत से घटाकर जी॰डी॰पी॰ का 5.1 प्रतिशत कर दिया है। 3जी की निलामी से छप्पर फाड़कर आमदनी हुई है। जिसके कारण राजकोषीय घाटा 5.5 से घटकर 5.1 प्रतिशत आ गया। इसमें वित्त मंत्री जी की करामात नहीं है। इसमें वित्तीय प्रबंधन की कोई करामात नहीं है। मिडटर्म पॉलिसी स्टेटमेंट जो दिया जाता है, उसमें भी इन्होंने यह स्वीकार किया है कि हम मुद्रा विस्तार की वजह से राजकोषीय घाटा कम रखने में सफल हुए।

अब आप जरा नॉन प्लान व्यय को देखें। सन् 2010–11 में इसका एस्टीमेट 7,35,657 करोड़ रुपये था। यह जब रिवाइज्ड हुआ तो 8,21,552 करोड़ हो गया। सन् 2011–12 में 8,16,182 करोड़ का अनुमान है। ये इतना रहेगा नहीं, ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। अगर आप प्लान व्यय को देखें तो सन् 2010–11 में 3,73,092 अनुमान था और रिवाइज 3,95,000 हुआ। सन् 2011–12 में एस्टीमेट 4,41,547 करोड़ था। इन सबके लिए रिसोर्सेस कहां से आएंगे? सरकार का इनफ्लेशन पर कोई नियंत्रण नहीं है। कच्चे तेल की कीमतें बेहिसाब बढ़ रही हैं और खाद्यान्नों के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसी हालत में यह कहना कि यह जो सन् 2011–12 का कुल खर्चा 12,57,729 करोड़ रखा गया है, पता ही नहीं यह आंकड़ा कहां जाएगा। फिर सरकार कहती है कि यह बजट रिफार्म्स का एक खाका पेश करेगा। सवाल यह है कि आपको रिफार्म चाहिए या अर्थव्यवस्था के मौलिक सिद्धांत ठीक करने चाहिए। अगर आप बजट को ठीक से देखें तो लगभग 4,70,000 करोड़ रुपए उधार के चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इससे चिंतित है। आर॰बी॰आई॰ कहता है कि लिक्विडिटी कम है। वह स्क्वीज हो रही है। अगर सरकार पैसा बाजार से उठा लेगी तो आम उद्योगों के लिए कहा से पैसा आएगा। उद्योग नॉन–कॉम्पीटीटिव हो जायेंगे। इसका असर एक्सपोर्ट पर होगा और 'इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सजेंज' कम होगा।

इससे महंगाई की आंच और तेज होगी। मंत्री जी ने कहा है कि वित्तीय प्रबंधन और विकास बड़े महत्वपूर्ण मसले हैं। मुझे दिखाई नहीं देता कि इसमें से आप कोई विकास कर पायेंगे या आप देश में महंगाई पर नियंत्रण कर पायेंगे। सरकार फूड सिक्योरिटी बिल को लाने की बात कर रही हैं और ले आई और लागू कर दिया, तो उसके लिए धन का कोई प्रावधान आपने इसमें नहीं किया है। मुझे बड़ी खुशी

होगी, अगर आप यह कर सकें लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप यह कर पायेंगे। सरकार सारे मॉनीटरी और फिस्कल तरीके अपनाकर महंगाई 8.23 परसेंट से घटाकर 4 या 5 परसेंट तक ले जाने की बात करती है। मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे ले आएगी? मुझे बहुत डर लग रहा है कि आपने जैसे ऊंची बातें कहीं हैं उन्हें आप पूरा कर पाएंगे या नहीं। वित्त मंत्री ने कहा कि कराधान के द्वारा, टैक्सेशन के द्वारा इस बार उन्होंने कोई रिसोर्स नहीं किया, तो वे पैसा कहां से लाएंगे, कहां से पैदा करेंगे? इसलिए इस बार आप कितना डिस–इन्वैस्टमेंट करेंगे, किस हद तक जाएंगे, यह भी साफ नहीं है। फिर आप कहेंगे कि एफ॰डी॰आई॰ और एफ॰आई॰आई॰ बढ़ाएंगे, एफ॰डी॰आई॰ लाएंगे। एफ॰आई॰आई॰ तो जहां ज्यादा पैसा दिखाई देता है वहां चले जाते हैं। आपका स्टॉक मार्केट उसे पैसा देगा तो यहां रहेंगे नहीं, कहीं और चले जायेंगे। आप चाहते हैं कि एफ॰डी॰आई॰ रिटेल सैक्टर में आ जाए। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप एफ॰डी॰आई॰ को कभी भी रिटेल में मत लाइये। हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था को आप तबाह मत कीजिए। इसमें सुधार कीजिए, इसमें सुधार के मैं खिलाफ नहीं हूं। अगर आप एक सफल वित्त मंत्री के नाते इस देश में कुछ करना चाहते है तो रिटेल को सुधारिये, इसको मजबूत कीजिए, क्योंकि यह हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आप घरेलू बचत बढ़ाकर अपने लिए रिसोर्सेज ला सकते हैं। रिजर्व बैंक भी कहता है कि घरेलू बचत बढ़ाइए। बढ़ते हुए करेंट एकाउंट डेफीसिट भी चिंता का विषय है। इसका सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था के स्थायित्व पर पड़ेगा। 21वीं शताब्दी में 'नॉलेज बेस्ड सोसाइटी' का समय है। अब ज्ञान को हम धन में परिवर्तित कर रहे हैं। ज्ञानाधृष्टित समाज बनाइए। लोगों को प्रशिक्षित कीजिए। टैक्नीकली एडवांस देश बनाइए और पेटैंट अधिक से अधिक कीजिए। अब केन्द्रीय बजट के एक और पहलू की तरफ ध्यान दीजिए। ये कॉरपोरेट इनकम टैक्स में हर रोज 245 करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लगभग इतनी ही राशि प्रतिदिन भारत से हवाला कारोबार द्वारा विदेशों में जा रही है। आपने वर्ष 2005–06 से आज तक जो कुल राजस्व छोड़ा है, वह 21 लाख 25 हजार 23 करोड़ रुपए है। यह आपने किसको दिया है? यह आपने कॉरपोरेट हाउसेज को दिया है। आप कहते हैं कि हमने एक्साइज इसलिए छोड़ी कि आम आदमी को राहत मिलेगी क्योंकि यह इनडायरैक्ट टैक्स है। क्या यह टैक्स आम आदमी तक गया है? यह कॉरपोरेट समाजवाद है। गरीब आदमी के नाम पर कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाना।

सूरत में कुछ लोगों ने डायमंड के क्षेत्र में आत्महत्या भी की थी। आपने अगर कस्टम ड्यूटी कम की है तो इसका फायदा उनको मिला। अगर मिला होता तो मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन आप गरीब के नाम पर कॉरपोरेट हाउस को लाभ पहुंचा रहे हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की रिपोर्ट के अनुसार इस देश से विदेशी बैंकों में अवैध ढंग से गया धन 462 बिलियन डालर आपने जो छूट बड़े घरानों को दी है, वहीं विदेशों में काले धन के रूप में जमा हो गयी है। यह क्या हो रहा है? यह वह धन है जो आपकी पॉलिसी के कारण जा रहा है। पी॰डी॰एस॰ को ठीक ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। अब तो कहा जा रहा है कि हम कैश ट्रांसफर करेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि कैश ट्रांसफर इस देश में कैसे हो सकता है? डिलीवरी का सिस्टम ठीक होना चाहिए। आज दुनिया की सबसे बड़ी भूखी जनसंख्या हिन्दुस्तान में है, उसको आप अनाज नहीं देना चाहते हैं। आज 37 देशों में फूड रॉयट्स हुए हैं। क्या आप भारत को भी उसी तरफ ढकेलना चाहते हैं कि आप अनाज पैदा मत करो? अनाज खेत में पैदा होता है, किसान पैदा करता है। उसके लिए जमीन, बीज, पानी, खाद आदि का इंतजाम करना पड़ता है। किसान को अच्छा दाम मिले, इसका इंतजाम करना पड़ता है। आपका इकोनोमिक सर्वे कहता है कि वर्ष 2009–10 में प्रति व्यक्ति अन्न की उपलब्धता वर्ष 1955 की तुलना में उससे कम है। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश में हमसे ज्यादा है। सबसे अधिक लोग खेती में यहां काम करते हैं, सरकार रोज खेती का नाम लेती है, मगर अन्न की उपलब्धता गिर रही है। मैल–न्यूट्रिशन्ड स्टेट बन रही है। मैल–न्यूट्रिशन्ड पापुलेशन महाशक्ति नहीं बन सकती।

आपका इकोनोमिक सर्वे कहता है कि पिछले सालों में

आपने वर्ष 2005–06 से आज तक जो कुल राजस्व छोड़ा है, वह 21 लाख 25 हजार 23 करोड़ रुपए है। यह आपने किसको दिया है? यह आपने कॉरपोरेट हाउसेज को दिया है। आप कहते हैं कि हमने एक्साइज इसलिए छोड़ी कि आम आदमी को राहत मिलेगी क्योंकि यह इनडायरैक्ट टैक्स है। क्या यह टैक्स आम आदमी तक गया है? यह कॉरपोरेट समाजवाद है। गरीब आदमी के नाम पर कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाना।

जितना पूंजी निवेश हुआ है देश की अर्थव्यवस्था में कृषि में केवल 7.5 प्रतिशत हुआ है और कृषि 58 प्रतिशत लोगों का जीवनयापन कराती है। आप वहां पूंजी निवेश कैसे बढाएंगे? अगर आप इस कॉरपोरेट छूट को उधर न देकर, उसका आधा हिस्सा भी इधर दे दें तो इस देश के किसान आपका गुण गाएंगे। कृषि का निवेश घट गया है, बढ़ा नहीं है। आपने 2007 में जो नेशनल फार्म पॉलिसी इन सदन में रखी थी उसकी घोर उपेक्षा की है। किसानों को एक सुनिश्चित आय का बंदोबस्त नहीं किया है। युवा किसानों को खेती को जीवन पद्धति और लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए आकृष्ट नहीं किया गया है। कुछ मित्रों ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के आसपास के गांवों का सर्वे किया, एक लाख लोगों से मिलने के बाद एक भी नौजवान नहीं मिला जो कृषि को अपनाना चाहता हो। क्यों? चीन और अमेरिका में बढ़ते हुए अन्न संकट को दोहराते हुए कहना चाहता हूं कि उसे अनदेखा न कीजिए। हमें चेतावनी दी गई कि 21वीं शताब्दी में विश्व को सबसे बड़े संकट का सामना जल संकट के रूप में करना पड़ेगा। जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण तथा पुनर्स्थापना के लिए बड़ी योजना आरंभ की गई थी। लेकिन किन निकायों का विकास हुआ है, किन एक्वाबाडीज़ का विकास हुआ है? कौन से तालाब ठीक किए गए हैं और कौन से कुएं ठीक किए गए हैं? जल का भारी संकट आने वाला है। पीने के पानी का भी और सिंचाई के जल का भी संकट आने वाला है। इसका जिक्र आपके बजट में नहीं है। पीने के पानी का क्या होगा, सिंचाई के पानी का क्या होगा? फूड प्राइस में जो आप स्पेकुलेशन करते हैं, कमोडिटी प्राइसेज़ उसे बंद कर दीजिए। आपने कहा है कि कृषि ऋण को जमा करने पर तीन परसेंट की छूट दी जाएगी यानि 7 परसेंट से घटकर 4 परसेंट हो जाएगी। जो बड़ा किसान है वहीं 7 परसेंट पर लोन लेता है, समय पर वापस कर देता है और तीन परसेंट की छूट ले लेता है। लेकिन छोटा किसान जो है उसका क्या हाल है? हमें पूरे आंकड़े चाहिए? हम आंकड़े चाहते हैं कि किसानों की आत्महत्या अभी तक बंद क्यों नहीं हुई? माननीय वित्त मंत्री जी आपकी नीति होनी चाहिए—ऋण मुक्त किसान, रोजगार युक्त ग्रामीण नौजवान, तब होगा भूख मुक्त और समृद्ध हिन्दुस्तान। 58 प्रतिशत लोगों के लिए कोई सामाजिक और स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। नेशनल रूरल मिशन की रिपोर्ट में सी.ए.जी. ने हैल्थ सेंटर्स के क्या हालात हैं पर टिप्पणी की है। सी.ए.जी. ने बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की बहुत दयनीय स्थिति पेश की है। आपके राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी का जिक्र नहीं है। पानी की रिपोर्ट तो और भी मजेदार है। एक्सलरैटिड इरिगेशन बैनीफिट के 44 प्रोजेक्ट हैं, जिनको बताया गया है कि कम्पलीट हो गए हैं और पैसा भी चला गया है। लेकिन इसमें पानी नहीं है। आप सोशल सैक्टर के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। आप सभी स्कीमों को रिस्ट्रक्चर कीजिए। बिना ऐसा किए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं एक निवेदन और कहना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी ने गुरू रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं वर्षगांठ के लिए बहुत कुछ कहा है। लेकिन आप पी.सी. राय को क्यों भूल गए? वह भी बंगाल के हैं। उन्होंने ही बंगाल कैमिकल की स्थापना की थी। आचार्य पी.सी. राय का काम रसायन शास्त्र के इतिहास के लिखने में कितना जबरदस्त है लेकिन आप उनको भूल गए। सरकार उनकी 150वीं वर्षगांठ के लिए एक समुचित प्रोग्राम की घोषणा क्यों नहीं कर रही है, इससे देश के वैज्ञानिकों में एक अच्छा संदेश जाएगा। पंडित मालवीय जी के लिए आपने क्या किया? मालवीय जी चार बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि दुनिया भारत के मॉडल की बहुत प्रशंसा करती है। लेकिन इस मॉडल को हम क्या करें जिसमें अनऑरगेनाइज्ड लेबर का हिस्सा नहीं है, जिसमें किसान पिस रहा है, जिसमें गरीबी बढ़ रही है, जिसमें डिसपैरिटी बढ़ रही है, जिसमें महंगाई बढ़ रही है। लेकिन मैं ऐसे विकास से सहमत नहीं हूं। जब तक कोई मॉडल इस देश की बड़ी आबादी के जीवनस्तर को ऊंचा नहीं उठाता देश को अस्वीकार्य है। इस मॉडल ने अमरीका और यूरोप को तबाह कर दिया। इस मॉडल से चीन भी बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है, उसने अपना मॉडल में सुधार किया। भारत को अपना मॉडल बनाना चाहिए। भारत के सामने जो आर्थिक विकास के मुद्दे हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। आपने आंगनवाड़ियों की मानदेय को बढ़ाया, अच्छा किया है और बढ़ना चाहिए। आपने एस.सी. और एस.टी. बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की स्कीम में कुछ इजाफा किया, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन आपने जम्मू–कश्मीर और लद्दाख में जो भेदभाव किया है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। आपने लद्दाख को 100 करोड़ दिए, बहुत अच्छा किया लेकिन जम्मू को सिर्फ 150 करोड़ क्यों दिए? मुझे इस बजट में कोई सराहनीय काम दिखाई नहीं देता है। इसमें गरीबों का कोई जिक्र नहीं है। मैं इस बजट के तमाम आंकड़ों और तमाम प्रस्तावों से बहुत चिंतित हूं। जैसा मैंने पहले कहा कि आप वित्तीय प्रबंध को ठीक कर सकें तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद दूंगा। लेकिन जो तथ्य हैं उन्हें देखकर संदेह होता है कि आप इसे पूरा कर सकेंगे।■

आम बजट

राज्यसभा

आम आदमी की उम्मीदों पर यूपीए ने पानी फेरा : रविशंकर प्रसाद

गत 9 मार्च को राज्यसभा में आम बजट (2011–12) पर चर्चा की शुरूआत करते हुए भाजपा सांसद श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पूरे देश को वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी से काफी उम्मीदें थीं लेकिन उन्होंने गरीबों सहित समाज के सभी वर्गों को बुरी तरह से निराश किया है। उन्होंने कहा कि समाज में आज जो विभिन्न अंतर दिखाई दे रहे हैं उनको पाटने के लिए बजट में कोई प्रस्ताव नहीं है। हम यहां भाजपा सांसद श्री रविशंकर प्रसाद, श्री प्रभात झा एवं श्री पीयूष गोयल के भाषण का सारांश प्रकाशित कर रहे हैं:–

Hkkरत के संदर्भ में बजट मात्र लेखाजोखा और खर्च की एक दस्तूरी प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह एक ऐसा वार्षिक दस्तावेज है जिसकी ओर लोग, गरीब लोग, व्यवसायीजन और अन्य सभी लोग बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे होते हैं। किंतु इस बार एनएसी के एक सदस्य तक ने भी यह कह दिया है कि इस बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है। मुद्रास्फीति की दर चिंता का विषय है। मूल्य–वृद्धि से न केवल गरीबों, अत्यधिक गरीबों बल्कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। आम आदमी परेशान है और केवल आश्वासन पर आश्वासन मिल रहे हैं। आर्थिक समीक्षा में भी यह बात स्वीकार की गई है कि पिछले 76 हफ्तों से अर्थात् जून 2009 से लेकर कीमतें ऊंची रही हैं। चावल, सब्जियां, आलू, प्याज, फल, दूध, मीट, मछली, चाय और मसाले आदि सभी चीजें महंगी हैं।

इस बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है। मुद्रास्फीति की दर चिंता का विषय है। मूल्य–वृद्धि से न केवल गरीबों, अत्यधिक गरीबों बल्कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। आम आदमी परेशान है और केवल आश्वासन पर आश्वासन मिल रहे हैं। आर्थिक समीक्षा में भी यह बात स्वीकार की गई है कि पिछले 76 हफ्तों से अर्थात् जून 2009 से लेकर कीमतें ऊंची रही हैं। चावल, सब्जियां, आलू, प्याज, फल, दूध, मीट, मछली, चाय और मसाले आदि सभी चीजें महंगी हैं।

आर्थिक समीक्षा के अनुसार एक भारतीय परिवार अपना 40 प्रतिशत खर्च केवल खाद्य मदों पर करता है। विकासशील देशों में यह प्रतिशत 7 से 8 तक का है। सबसे अधिक रोचक बात यह है कि ये आँकड़े थोक मूल्य सूचकांक से संबंधित हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तो जिक्र ही नहीं किया गया है। मंहगाई के लिए यह तर्क दिया जा रहा है कि लोग ज्यादा खा रहे हैं और इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं। यह बात न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि बहुत खेदजनक भी है। भारत में किशोर–बच्चों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है और इसमें से 47 प्रतिशत 'अंडरवेट' हैं और 56 प्रतिशत खून की कमी से ग्रस्त हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 80 प्रतिशत बच्चे, 70 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं और 24 प्रतिशत पुरूष कुपोषण के शिकार हैं। देश के स्वास्थ्य, गरीब लोगों के स्वास्थ्य की यह हालत है। फिर भी जब यह कहा जाता है कि लोग ज्यादा खा रहे हैं और इसलिए कीमतें बढ़ रही है तो मेरा मानना है कि यह बहुत दुःखद बात है।

एक अन्य तर्क यह है कि त्वरित आर्थिक विकास से भी महंगाई बढ़ती है। इस संबंध में यदि आँकड़ों की तुलना अन्य देशों के आँकड़ों से की जाए तो हमें पता चलता है कि यह सही और तथ्यपरक स्थिति नहीं है। यह पूरा तर्क कि मूल्य वृद्धि विकास का एक अभिन्न अंग है, स्वीकार्य नहीं है। वस्तुतः, 2005 और 2010 के बीच सभी वस्तुओं की कीमतें 38 प्रतिशत बढ़ी थीं जबकि खाद्य मदों की कीमतों में 77 प्रतिशत से भी अधिक उछाल आया था। 'राजग' के शासन

काल में भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया था। अब हम एक स्थिति से जूझ रहे हैं कि हमें दूध आयात करना पड़ रहा है। इतना बड़ा कुप्रबंधन क्यों है? बजट भाषण के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का स्टॉक 470 लाख मिट्रिक टन पहुंचा था। किंतु भारत में कुल खाद्य भंडारण क्षमता लगभग 200 लाख मिट्रिक टन है। इसका मतलब है कि केन्द्रीय पूल में आधे से अधिक खाद्यान्नों का भंडार भंडारण क्षमता से बाहर पड़ा था और सड़ रहा था। इसे जनता के लिए जारी नहीं किया जा रहा है और उसे सड़ने दिया जा रहा है। यह खाद्य कुप्रबंधन का एक गंभीर मामला है जिस पर मेरे विचार से एक अति स्पष्ट जवाब दिए जाने की जरूरत है।

पूरे बजट में देश में बेरोजगारी और उसे दूर किए जाने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। रोजगार को बढ़ावा देने के मामले में विनिर्माण क्षेत्र की एक बड़ी भूमिका होती है किंतु उसमें मंदी चल रही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस देश में 'संप्रग–I' और 'संप्रग–II' के शासनकाल में कितना रोजगार सृजित किया गया है? भारत में बेरोजगारी की दर 2004–05 की 8.3 से बढ़कर 2009–10 में 9.4 हो गई।

अब मैं कृषि क्षेत्र पर आता हूं। भारत की 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है और इसमें देश में 58 प्रतिशत रोजगार देने की क्षमता है। फिर भी इसका जीडीपी का घटक केवल 14.6 प्रतिशत है। यह देश की संपूर्ण आर्थिक संरचना में एक गंभीर असंतुलन की स्थिति है। अब यदि सिंचाई के लिए केंद्रीय आवंटन को देंखे तो यह केवल 565 करोड़ रूपए है जो कि बहुत ही कम है। जब तक कृषि को भारतीय जीडीपी का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं माना जाता, तब तक कृषि को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी जाएगी जो कि उसे मिलनी चाहिए। मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस बजट में ऐसी कोई बड़ी बात दिखाई नहीं देती। दूसरी हरित क्रांति के अंतर्गत आपने छः क्षेत्रों में 60,000 गाँवों को निर्धारित किया है जिनमें से प्रत्येक को 300 करोड़ रूपए दिए गए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि एक गांव को मात्र 50 हजार रूपए मिलेंगे जो कि पर्याप्त नहीं है। हमें मालूम है कि कृषि राज्य का विषय है किंतु इसमें सरकार की ओर से भी पहल होनी चाहिए। हमने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए सब्सिडी को नकद में अंतरित करने का निर्णय लिया है। हम यह जानना चाहते हैं कि देश में गरीब अथवा गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं क्योंकि विभिन्न निकायों द्वारा विभिन्न आँकड़े दिए गए हैं। 'संप्रग' सरकार के अन्तर्गत विकास की कहानी यह है कि गरीब और गरीब हो रहे हैं तथा अमीर और अमीर हो रहे हैं।

हम विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका का समर्थन करते हैं क्योंकि सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। हम उद्यम लगाए जाने की भी सराहना करते हैं। किंतु यदि आप एक ऐसी व्यवस्था देंगे जिसमें कुछ लोग तो बहुत ज्यादा धन–संपत्तियां जुटा लेंगे और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनता का एक बड़ा हिस्सा मुश्किलों का सामना कर रहा है और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो इस तरह की व्यवस्था हमें स्वीकार्य नहीं है। आपको इस मुद्दे पर ध्यान देना होगा। यह कोई समावेशी विकास नहीं है। अब मैं स्वास्थ्य के मुद्दे पर आता हूं। इस बजट का सबसे खराब घटक यह है कि स्वास्थ्य सुरक्षा पर 5 प्रतिशत सेवा कर थोप दिया गया है। हम स्वास्थ्य सुरक्षा पर जीडीपी का मात्र एक प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। सार्वजनिक अवसंरचना की स्थिति एकदम असंतोषजनक है। स्वास्थ्य पर 80 प्रतिशत खर्च की राशि इस देश के लोगों के अपने संसाधनों से आती है। अब समय आ गया है कि स्वास्थ्य सुरक्षा को अवसंरचना का ही एक हिस्सा माना जाए। पूरे बजट में देश में बेरोजगारी और उसे दूर किए जाने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। रोजगार को बढ़ावा देने के मामले में विनिर्माण क्षेत्र की एक बड़ी भूमिका होती है किंतु उसमें मंदी चल रही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस देश में 'संप्रग–I' और 'संप्रग–II' के शासनकाल में कितना रोजगार सृजित किया गया है? भारत में बेरोजगारी की दर 2004–05 की 8.3 से बढ़कर 2009–10 में 9.4 हो गई। अब में अवंसरचना क्षेत्र पर आता हूँ। आपने आर्थिक सर्वेक्षण में यह स्वीकार किया है कि यह एक दुःखद गाथा है। राष्ट्रीय राजमार्ग का मामला लें। हमें इस पर गर्व था। यह 'राजग' शासन की सफलता की महान गाथा थी। राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम की स्वर्णिम अवधि थी। इस दौरान स्वर्णिम चतुर्भुज का 71 प्रतिशत कार्य पूरा किया गया।

पूर्वी–पश्चिमी गलियारे का कार्य भी बहुत उत्तम चल रहा था। लेकिन, अब हमें यह सुनाई देता है कि सीबीआई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) पर छापे मार रही है। उसके महाप्रबंधकों, उप महाप्रबंधकों, अवर

सचिवों इत्यादि को जेल में डाला जा रहा है।

यह क्या हो रहा है? जब तक हमारे पास अच्छी अवसंरचना नहीं होगी, तो क्या भारत आपके अनुमान के अनुसार विकास कर सकता है? रोजगार सृजन के विकास का एक अन्य क्षेत्र आवास क्षेत्र है। किंतु इसके लिए संसाधनों की कमी है। गरीबों के लिए आवास की कोई योजना नहीं है। आपको वित्तीय घाटा 4.6 प्रतिशत करना होगा। पिछले वित्तीय वर्ष में 5.5 के बजट अनुमान की तुलना में वित्तीय घाटा 5.1 पर आ गया था। ऐसा क्यों हुआ? इसका प्राथमिक कारण यह है कि 3जी की नीलामी से बेतहाशा आय प्राप्त हुई थी। आप इसको कैसे कम करने जा रहे हैं? मुझे सबसे अधिक परेशान आपके इस दृष्टिकोण ने किया है कि आप राज–सहायता कम करना चाहते हैं। जी हाँ, यह कम हो सकती है बशर्ते गरीबों की जरूरतों को पूरा कर दिया जाए। लेकिन अभी क्या परिदृश्य है? आयकर माफी, विभिन्न प्रकार के केन्द्रीय करों में माफी आदि के आधार पर कॉरपोरेट क्षेत्र के करों को बट्टे–खाते में डाला जा रहा है। गरीबों की राज–सहायता कम की जा रही है और निगमित क्षेत्र के करों को बट्टे खाते में डालने की गति बढ़ रही है। आपके भाषण में विदेशों में जमा काले धन के मुद्दे पर हमें सबसे अधिक निराशा हुई है। क्या यह केवल एक कर देयता है या एक अपराध है? यह अपराध विभिन्न प्रकार की धनशोधन और अन्य आपराधिक गतिविधियों का फल है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने दोहरे कराधान और कर विनिमय सूचना समझौते के संबंध में दो मुद्दे उठाये थे। आपको विदेशों में गैर–कानूनी रूप से एक व्यक्ति द्वारा जमा की गई भारत की अरबों रुपये की धनराशि के मामले में कार्रवाई करने के लिए उच्चतम न्यायालय की एक कठोर टिप्पणी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भारत सरकार की जानकारी के अनुसार भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशी बैंकों में लगभग कुल कितना धन जमा किया गया है? इस धन का संबंध किन–किन व्यक्तियों और कम्पनियों से है और इनमें से कितनों के विरूद्ध किसी न किसी प्रकार का आपराधिक अभियोजन आरंभ कर दिया गया है? हम यह जानना चाहेंगे कि विदेशी बैंकों को कितनी जानकारी प्रदान की गई है? हम यह जानना चाहेंगे कि 1200 मामलों में से कितने मामलों में विदेशी बैंकों को जानकारी दी गई है। दूसरी बात यह है कि भारत ने 'यू.एन. कन्वेंशन अंगेस्ट करप्शन' की पुष्टि अभी तक क्यों नहीं की है? मैं यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे स्विट्जरलैंड समेत विभिन्न देशों से हम सहयोग प्राप्त करने में समर्थ हो पायेंगे।

मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने इस बजट में 77 प्रतिशत गरीबी के नीचे जो लोग जीते हैं उनके लिए आपने क्या दिया है? 15 लाख बच्चे कुपोषित होते हैं और हर साल मर जाते हैं। 44 करोड़ असंगठित कामगार हैं। उनके लिए आपने इस बजट में क्या दिया है? महिला, किसान, नौजवान किसी के लिए कुछ भी नहीं है। आपने किसान की बात की है, 7 प्रतिशत पर आप ब्याज देंगे।

इस बजट में मध्यम वर्ग की उपेक्षा की गई है। जब अगले वर्ष से प्रत्यक्ष कर संहिता लागू होने जा रही है, तो आप स्वयं इस वर्ष से आय सीमा को दो लाख रुपये तक बढ़ा सकते थे। यह 2,000 रुपये की अल्प बचत सतत मुद्रास्फीति द्वारा बट्टे–खाते में डाल दी जायेगी। जी.एस.टी. देश के लिए अच्छा है। किंतु हमें यह अवश्य ही सुनिश्चित करना होगा कि इसे इस तरीके से संचालित किया जाए कि राज्यों के वित्तीय हितों को किसी प्रकार का नुकसान न हो। देश में सुधार कार्यक्रमों की भी आवश्यकता है। अभी भी कई क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। हम यह आशा करते हैं कि सरकार इसके लिए विपक्ष के पास आयेगी।

इस बजट से बहुत आशाएं थी परंतु दुर्भाग्यवश, इसने सभी आशाओं को झुठला दिया है और इसमें कोई दृष्टिकोण, दूरदर्शिता, ध्यान, राजनीतिक पहल या प्रेरणा नहीं है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों, जैसे विद्युत उत्पादन, राजमार्ग निर्माण, कच्चे तेल के उत्पादन, कोयला उत्पादन, महापत्तनों की क्षमता में वृद्धि इत्यादि में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कम सफलता हासिल की है। इस सरकार का निष्पादन क्या है? उनके पास साक्षरता, शिक्षा और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा देने के लिए कोई ठोस रूपरेखा नहीं है।

बजट से परेशान किसान व नौजवान – प्रभात झा

यह बजट कोई आम बजट नहीं है क्योंकि इस देश के आम लोगों के लिए इसमें कुछ नहीं है। सरकार की कोई साख नहीं है और इसलिए कोई धाक भी नहीं है। आज संप्रग सरकार की हालत यह है कि देश में अनेक घोटाले हो रहे हैं और उनके मंत्री जेल में हैं। सीवीसी का मामला चल रहा है और कांग्रेस पार्टी को गठबंधन दलों से धमकियां मिल रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है और इसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने इस बजट में 77 प्रतिशत गरीबी के नीचे जो लोग जीते हैं उनके लिए आपने क्या दिया है? 15 लाख बच्चे कुपोषित होते हैं और हर साल मर जाते हैं। 44 करोड़ असंगठित कामगार हैं। उनके लिए आपने इस बजट में क्या दिया है? महिला, किसान, नौजवान किसी के लिए कुछ भी नहीं है। आपने किसान की बात की है, 7 प्रतिशत पर आप ब्याज देंगे। मध्य प्रदेश की भाजपा शासित सरकार ने इसी वित्त वर्ष से एक प्रतिशत ब्याज पर किसानों के लिए बजट आवंटित भी किया है। 'संप्रग' की सरकार महंगाई के लिए उच्च विकास दर को दोषी ठहराती है। महंगाई और आर्थिक विकास दर में कोई संबंध नहीं है। इस समय भारत में जो महंगाई का दौर चल रहा है उसका मूल उच्च विकास दर नहीं, बल्कि यह खाद्य पदार्थों के मूल्यों के कारण से हुई है। सरकार कहती है कि दलितों और आदिवासियों के लिए हम बहुत काम करते हैं। किन्तु, इस बजट में 27 करोड़ रुपया आपने क्यों कम कर दिया? इसका जबाव सदन चाहता है। केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा पर सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत खर्च करती है, जो अपर्याप्त है। पिछले दो वर्षों में विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत बजट आवंटन के लिए 14 प्रतिशत की कटौती की गई। हम सभी जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है? ऐसे में आम बजट में नैदानिक जांच कराने पर पांच प्रतिशत का सेवा कर लगा दिया गया है। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में ऐलान किया है कि उनकी सरकार खाद्य सुरक्षा कानून बनायेगी। क्या इस बजट में कोई प्रावधान किया है? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारतीय बैंकों में ऐसे अरबों रुपये आज पड़े हुए हैं, जिन पर किसी का दावा नहीं है। एक आरटीआई के जवाब में भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि भारतीय बैंकों में 1300 करोड़ से ज्यादा रुपये जमा हैं। मेरे पास उन बैंक खातों के नाम हैं, जिनमें यह कालाधन जमा हैं। हम जानना चाहते हैं कि अगर आप स्विस बैंक का पैसा वापस नहीं ला पा रहे हैं, तो भारत में जमा ये काला धन आप क्यों नहीं निकालना चाहते हैं?

ठोस रूपरेखा का अभाव : पीयूष गोयल

बस बजट से बहुत आशाएं थी परंतु दुर्भाग्यवश, इसने सभी आशाओं को झुठला दिया है और इसमें कोई दृष्टिकोण, दूरदर्शिता, ध्यान, राजनीतिक पहल या प्रेरणा नहीं है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों, जैसे विद्युत उत्पादन, राजमार्ग निर्माण, कच्चे तेल के उत्पादन, कोयला उत्पादन, महापत्तनों की क्षमता में वृद्धि इत्यादि में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कम सफलता हासिल की है।

इस सरकार का उपलब्धि क्या है? उनके पास साक्षरता, शिक्षा और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा देने के लिए कोई ठोस रूपरेखा नहीं है। यह कहा गया है कि 'मनरेगा' योजना इस देश के लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है। क्या इसी प्रकार का रोजगार यह सरकार लोगों को देना चाहती है? वे परिसंपत्तियां क्या हैं, जिन्हें सृजित किया जा रहा है?

सरकार 'मनरेगा' के क्रियान्वयन के संबंध में शेखी बघार रही है। अपने क्रियान्वयन को देखो। वे काले धन को वापस लाने के संबंध में बात करते हैं। परंतु जो

शेष पृष्ठ 29 पर

आम आदमी की दृष्टि में आम बजट

✍ IR; iky

यह विडम्बना है कि देश का जो वार्षिक आम बजट आम जनता के लिए होना चाहिए उसी से आम आदमी दूर रहता है। सच तो यह है कि बजट बड़े–बड़े अर्थशास्त्री बनाते हैं, जो कुछ दिग्गजों और बुद्धिजीवियों की समझ में आता है। देश के आम आदमी को तो बजट से प्रभावित होने वाली अनुभूतियों को ही महसूस करना होता है। आम आदमी को यह क्या पता कि देश का बजट कितने अरबों–खरबों का है, राजकोषीय घाटा क्या है? विकास प्रतिशत 8 प्रतिशत रहेगी या 9 प्रतिशत, जीडीपी किस बला का नाम है? आदि–आदि। उसका तो सीधा–मतलब इतनी बात से रहता है कि उसके जीवन का रहन–सहन बढ़ा या घटा है? मोटे तौर पर इसका सीधा संबंध महंगाई से है और आम आदमी इतना जरूर समझने लगा है कि सरकार ने इसे कम करने या बढ़ाने में कैसे और कितने कदम उठाए हैं।

हमें लगता है कि आम आदमी की दृष्टि से सरकार का बजट निर्माण करते हुए महंगाई पर काबू पाना सर्वोच्च प्राथमिकता रहनी चाहिए और उसकी दूसरी प्राथमिकता विकास होना चाहिए। जब तक इन दोनों में संतुलन नहीं बैठाया जाएगा तो महंगाई का बढ़ना अवश्यंभावी है क्योंकि अंधाधुंध विकास को प्राथमिकता देना, जैसा कि हमारे सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री विकास पर जोर देने की बात करते भी हैं, तो मुद्रास्फीति बढ़ती चली जाएगी अर्थात् महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी निर्धन से और निर्धनतम होता जाएगा। दुर्भाग्य यही है कि देश में अधिकांश काल तक कांग्रेस का शासन रहा और उसका रूख कभी भी गरीब और आम आदमी के साथ नहीं रहा, भले ही वह अपने नारों में लोगों को यह कहकर छलती रही कि हम आम आदमी के साथ हैं। इन्दिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और सत्ता में आते ही यह भी कह दिया कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है कि हम गरीबी मिटा दें। फलतः गरीब मिट गया, गरीबी नहीं। अब सोनिया गांधी ने 'कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ' का नारा दिया। अब उन्हीं के प्रधानमंत्री 'महंगाई' के बारे में ठीक यही बात दोहरा रहे हैं। कांग्रेस का विकास पर जोर देने का एक कारण रहा है कि विकास में सड़क, बिजली, परिवहन जैसी चीजें बड़े–बड़े कार्पोरेट क्षेत्रों, ठेकेदारों आदि के पास रहती है, जहां से भ्रष्टाचार पनपता है और सत्ता में बैठे लोगों को लाखों की बात तो दूर, अब तो यह भ्रष्टाचार का जाल अरबों–खरबों तक जा पहुंचने की नौबत आ गई है। इन सत्ताधारी राजनीतिज्ञों की कुशल मानसिकता ने अपने इन अरबों रुपयों को विदेशों में जमा कर काला धन पैदा कर दिया है, भले ही देश का सर्वनाश हो जाए।

अब एक प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर हम आम आदमी किसको मानते हैं। आज भी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे व्यक्ति को तो बजट से मतलब होता नहीं है, क्योंकि उसे तो रोज कुआं खोदना और पेट भरना होता है। इससे ऊपर अल्पआय वर्ग और मध्यम वर्ग आता है जिनमें छोटे व्यवसायी, अल्पवेतनभोगी और सरकारी कर्मचारी आदि शामिल रहते हैं। इन्हीं का सर्वाधिक प्रतिशत रहता है जिनका बजट से उभरी महंगाई या इसमें थोड़ी बहुत कमी होने का प्रभाव पड़ता है। शेष में तो कार्पोरेट क्षेत्र, दिग्गज राजनीतिज्ञ, संभ्रांत अधिकारीगण को ले सकते हैं, जिस पर महंगाई शिखर पर भी पहुंच जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के तौर पर पैट्रोल के दाम बढ़ जाएं तो कंपनी अपनी कंपनी के खाते में डाल देगी और अन्य सत्ताधारीगण आदि भी सरकार पर बोझा बन कर सरकारी खजाने को ही क्षति पहुंचाएंगे।

जैसा पहले कहा गया है कि हम यहां केवल आम आदमी की दृष्टि से बजट को देख रहे है, इसलिए बजट पर कितने लाखों अरबों रुपये खर्च होंगे, उन्हें किन–किन क्षेत्रों में बांटा जाएगा, विकास दर क्या होगी? राजस्व

दुर्भाग्य यही है कि देश में अधिकांश काल तक कांग्रेस का शासन रहा और उसका रूख कभी भी गरीब और आम आदमी के साथ नहीं रहा, भले ही वह अपने नारों में लोगों को यह कहकर छलती रही कि हम आम आदमी के साथ हैं। इन्दिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और सत्ता में आते ही यह भी कह दिया कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है कि हम गरीबी मिटा दें। फलतः गरीब मिट गया, गरीबी नहीं।

या राजकोषीय घाटा कितना बढ़ेगा? जीडीपी क्या होगी?– इन सब पर विचार न कर आम आदमी पर पड़ने वाले प्रभाव मात्र को देखेंगे।

अब वित्तमंत्री प्रणव दा ने अपने भाषण के शुरू में ही कह दिया कि महंगाई चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी क्या उन्होंने इस बजट में महंगाई कम करने का जरा भी प्रयास किया है, क्या कोई ऐसे कदम या कठोर कदम उठाए हैं जिससे मुद्रा–स्फीति रूके और उनकी चिंता निवारण का पता लग सके। वहीं बड़े–बड़े अर्थशास्त्री, दिग्गजों, बुद्धिजीवियों और यहां तक कि राहुल बजाज जैसे उद्योगपति भी यह कहने से नहीं चुके हैं कि वित्तमंत्री ने अपने आंकडों की जादूगरी मात्र दिखाई है। और पूरा बजट ही देश को गुमराह करने वाला है,जिससे आम आदमी महंगाई की मार झेल नहीं पाएगा।

यह पूरा का पूरा बजट ही एक छलावा है। यह बात हम विपक्षी दलों के राजनीतिज्ञों के हवाले से नहीं कह रहे हैं। ये वे लोग हैं जो बजट को बजट की तरह समझने वाले बुद्धिजीवी हैं। क्योंकि अब यह कहना कि वर्तमान विकास दर 8.1प्रतिशत है, आगे यह 9 प्रतिशत हो जाएगी, एफडीआई में निवेश बढ़ेगा, सरकारी खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी है, 2010–11 में देश की अच्छी प्रगति हुई है–ऐसी अनेक बातों से आज की बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के वातावरण में कोई कह सकेगा कि 'हम सुख से जी रहे हैं।'

अब देखिए, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए जो पुरानी स्थिति थी वह लगभग वैसी ही रखी है जब कि सरकार स्वयं मान रही है कि महंगाई आठ गुना बढ़ चुकी है। ऐसे में 1,60,000 रुपये से बढ़ाकर 1,80,000 रुपये करना, महिलाओं के लिए वही पुरानी स्थिति 1,90,000 रुपये रखना और सीनियर सिटीजन के लिए 2,40,000 रुपये से बढ़ाकर 2,50,000 रुपये की सीमा निर्धारित करना– क्या वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ मजाक नहीं है? शायद यह बात आपके ध्यान में न आए कि महंगाई भत्ते के बढ़ने के कारण जितनी आय बढती है, उस पर भी तो सरकार टैक्स वसूल करती है, जिससे सचमुच उसकी क्रय क्षमता का ह्रास होता है। इतना है नहीं, आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती महंगाई और पैट्रोल की आसमान छूती कीमतों एवं रिहायशी मकानों के किराए में वृद्धि के कारण तो उनका जीना दूभर हो जाएगा। स्थानाभाव को देखते हुए सभी महंगी होने वाली चीजों के नाम न गिनाकर रेडीमेड कपड़ों, सीमेंट, स्टेशनरी, अस्पताल में बीमारी खर्च आदि का गिनाना काफी है, जिससे आम आदमी का जीवनयापन गहरे संकट में फंस गया है। यह और भी विचित्र बात है कि सीमेंट के कच्चे माल पर रियायत दी गई है फिर भी सीमेंट महंगा होगा। वित्तमंत्री ने 130 उत्पादों को कर के दायरे में लाया है, जो महंगाई ही बढ़ाएगा और इससे भी ऊपर वित्तमंत्री ने रसोई गैस में सब्सिडी खत्म करने के जो संकेत दिऐ हैं, जिससे संभवतः एक सिलण्डर 700 रुपये तक जा पहुंचे तो ध्यान दीजिए गृहणियों का क्या होगा और वह कैसे अपनी रसोई का बजट संभाल पाएंगी जब कि सभी प्रकार की दालों, चीनी, खाद्य तेल, सब्जियां पराकाष्ठा पर पहुंची हुई हैं।

हां, अतिवरिष्ठ जनों पर प्रणव दा ने जरूर कृपा की है कि उन्होंने 80 वर्ष से ऊपर के लोगों को 5 लाख आय को कर से मुक्त किया है। यह उन बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से अच्छा कदम है जिनकी कोई देखभाल करने वाला न हो। और आज के समाज में ऐसे दृश्य दिखाई भी पड़ते हैं। परन्तु प्रणव दा को इससे कोई बहुत बड़ी राजस्व हानि होने वाली नहीं है। शायद

यह पूरा का पूरा बजट ही एक छलावा है। यह बात हम विपक्षी दलों के राजनीतिज्ञों के हवाले से नहीं कह रहे हैं। ये वे लोग हैं जो बजट को बजट की तरह समझने वाले बुद्धिजीवी हैं। क्योंकि अब यह कहना कि वर्तमान विकास दर 8.1प्रतिशत है, आगे यह 9 प्रतिशत हो जाएगी, एफडीआई में निवेश बढ़ेगा, सरकारी खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी है, 2010–11 में देश की अच्छी प्रगति हुई है–ऐसी अनेक बातों से आज की बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के वातावरण में कोई कह सकेगा कि 'हम सुख से जी रहे हैं।'

प्रणव दा को ऐसा बजट पेश करना चाहिए था, जिससे बेलगाम महंगाई पर लगाम लगती, भ्रष्टाचार खत्म होता और वह अपार–विशाल काला धन, जो विदेशों में पड़ा है, उसे देश में लाते जिससे पूरे देश की कायापलट होती। काले धन पर क्या कमाल की चीज हुई कि एक पांच सूत्री कार्यक्रम का गठन कर एक समूह बना दिया गया है, यानी आपने काला धन देश में न आए, इसकी एक जुगत बना ली है।

इसलिए वे यह कृपा कर बैठे हैं, फिर भी वे धन्यवाद के पात्र हैं।

प्रणव दा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की दुगनी आय की है, दूध उत्पादन, सामाजिक सर्वशिक्षा अभियान आदि में भी बढोतरी की है, लेकिन उसे भी अर्थशास्त्रियों ने अपर्याप्त माना है।

किसानों के लिए 4.75 लाख करोड़ रुपये का ऋण देने की व्यवथा की है। किन्तु इसे 7 प्रतिशत ब्याज पर दिया जाएगा। किन्तु जो लोग समय पर ब्याज की अदायगी कर देंगे तो उनके लिए 3 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जाएगा। भाजपा ने अपने शासन के समय पहले ही किसानों को 4 प्रतिशत पर ऋण दिया था और अब भी भाजपा की प्रत्यक्ष यही मांग रही है। लेकिन तथ्य यही है कि डिस्काउंट वाली बात को छोड़ दें तो किसानों को ऋण तो 7 प्रतिशत पर ही मिलेगा।

कार्पोरेट और समाचार पत्रों में आया है कि कार्पोरेट क्षेत्र और उद्योगपतियों ने बजट की प्रशंसा की है। बजट में जो वस्तुएं या उत्पादन सस्ते होंगे उनमें एलसीडी, टीवी, आभूषण, कागज, गाड़ियों के पुर्जे, सीमेंट उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल आदि शामिल हैं। स्पष्ट है,इन सब पर बड़े निवेश की जरूरत होती है और ये सभी ऐसी चीजें हैं जिनमें लाभ का प्रतिशत दो अंकों के प्रतिशत में नहीं ,बल्कि तीन अंकों के प्रतिशत में मुनाफा कमाकर तिजोरियां भरी जाती हैं, क्या इससे देश की समृद्धि बढ़ेगी? यह तो आप अपने इस बजट से गरीब और अमीर की आय में अंतर पैदा कर समाज में भेदभाव का जहर घोल रहे हैं।

प्रणव दा को ऐसा बजट पेश करना चाहिए था, जिससे बेलगाम महंगाई पर लगाम लगती, भ्रष्टाचार खत्म होता और वह अपार– विशाल काला धन, जो विदेशों में पड़ा है, उसे देश में लाते जिससे पूरे देश की कायापलट होती। काले धन पर क्या कमाल की चीज हुई कि एक पांच सूत्री कार्यक्रम का गठन कर एक समूह बना दिया गया है, यानी आपने काला धन देश में न आए, इसकी एक जुगत बना ली है। हमने इसी प्रकार के अन्य विषयों पर अनेकों समूहों के निष्कर्षों और उन पर की गई कार्यवाही की दुर्दशा हर बार होते देखी है। प्रणव दा का यह बजट पाखण्डपूर्ण, छलावा, आंकडों की जादूगरी के अलावा इस वर्ष होने वाले चुनावों के मद्देनज़र भी बनाया गया, जिसका उदाहरण हमें रविन्द्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती पर भाईचारा भावना बढ़ाने के लिए एक करोड़ रुपये के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तथा चुनावी दृष्टि से कुछ अन्य चुना की राज्यों में दी गई रियायतों में देखने को मिलता है।

प्रणव दा का यह बजट देश में फैली सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुधारने, अर्थव्यवस्था का उद्धार करने, महंगाई रोकने, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने, राजकोषीय घाटे को कम करने आदि किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करती है। आंकड़ों की जादूगरी भरमा जरूर सकती है, देश के निर्धनतम व्यक्ति का कल्याण नहीं कर सकती। अंत में इतना कहना काफी होगा–

i.ko nk dk ctV rjh vtc dgkuh]
fodkl jgk fu"Qy vkj cekuhA
egxkb] Hk"Vkpkj] dkykèku xkn e cBk]
Lo;a dg jgk viuh dgkuhAA ■

कमल संदेश के सुधी पाठकों को नवसंवत्सर 2068 की हार्दिक शुभकामनाएं

कमल सखी मंच की बैठक सम्पन्न

संसद के प्रत्येक सत्र के दौरान कम से कम एक बैठक आयोजित करने की परंपरा निभाते हुए कमल सखी मंच की संरक्षक श्रीमती कमला आडवाणी ने भाजपा सांसदों के पारिवारिक सदस्यों तथा महिला सांसदों ने (कमल सखी मंच) की एक बैठक 1 मार्च 2011को बुलायी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्रीमती सुषमा स्वराज, राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री राम लाल, श्रीमती कमला अडवाणी, श्रीमती सुमित्रा महाजन, श्रीमती नज़मा हेप्पतुल्ला, श्रीमती संतोष शैलजा, श्रीमती मायासिंह, श्रीमती संगीता जेटली, श्रीमती सावित्री सिंह, श्री यशोधरा राज सिंधिया, श्रीमती स्मृति ईरानी तथा अन्य परिवार के सदस्य उपस्थित थे। मंच की संयोजिका श्रीमती प्राची जावड़ेकर ने एक संक्षिप्त उद्बोधन में ऐसे मंच निर्माण एवं बैठक के उद्देश्यों को बताते हुए कहा कि इन बैठकों में विगत के अनुभव एक दूसरे के साथ बांटे जाएंगे। ■

भारतीय जनता पार्टी : एक संक्षिप्त इतिहास

& MK- f'ko 'kfDr cDlh

Hkkरतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने को कृतसंकल्प है। भारत को एक समर्थ राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ भाजपा का गठन 6 अप्रैल 1980 को कोटला मैदान, नई दिल्ली में एक कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी निर्वाचित हुए। अपनी स्थापना के साथ ही भाजपा ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं लोकहित के विषयों पर मुखर रहते हुए भारतीय लोकतंत्र में अपनी सशक्त भागीदारी दर्ज की तथा भारतीय राजनीति को नए आयाम दिए। कांग्रेस की एकाधिकार वाली एक–दलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जानी जाने वाली भारतीय राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने दो–ध्रुवीय बनाकर एक गठबंधन–युग के सूत्रपात में अग्रणी भूमिका निभाई है। देश में विकास आधारित राजनीति की नींव भी भाजपा ने विभिन्न राज्यों में सत्ता में आने के बाद तथा पूरे देश में भाजपा–नीत–राजग शासन के दौरान रखी। पिछले दो दशकों में भाजपा ने एक सशक्त राजनीतिक दल के रूप में देश में अपनी पहचान बनाई है।

पृष्ठभूमि

हालांकि भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ परन्तु इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता तथा देश के विभाजन के साथ ही देश में एक नई राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हुई। गांधी जी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाकर देश में एक नए राजनीतिक षड्यंत्र को रचा जाने लगा। सरदार पटेल के देहावसान के पश्चात कांग्रेस में नेहरू का अधिनायकवाद प्रबल होने लगा। गांधी और पटेल दोनों के नहीं रहने के कारण कांग्रेस 'नेहरूवाद' के चपेट में आ गई तथा अल्पसंख्यक तुष्टिकरण, लाइसेंस–परमिट–कोटा राज, राष्ट्रीय सुरक्षा पर लापरवाही, राष्ट्रीय मसलों जैसे कश्मीर आदि पर घुटना टेक नीति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारतीय हितों की अनदेखी आदि अनेक विषय देश में राष्ट्रवादी नागरिकों को उद्विग्न करने लगी। 'नेहरूवाद' तथा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिन्दू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर भारत के चुप रहने से क्षुब्ध होकर डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ स्वयंसेवकों ने भी प्रतिबंध के दंश को झेलते हुए महसूस किया कि संघ के राजनीतिक क्षेत्र से सिद्धांततः दूरी बनाये रखने के कारण वे अलग–थलग तो पड़ ही गए थे साथ ही संघ को राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल की आवश्यकता देश में महसूस की जाने लगी। फलतः भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में राघोमल आर्य कन्या उच्च विद्यालय, दिल्ली में हुई।

अपनी स्थापना के साथ ही भाजपा ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं लोकहित के विषयों पर मुखर रहते हुए भारतीय लोकतंत्र में अपनी सशक्त भागीदारी दर्ज की तथा भारतीय राजनीति को नए आयाम दिए। देश में विकास आधारित राजनीति की नींव भी भाजपा ने विभिन्न राज्यों में सत्ता में आने के बाद तथा पूरे देश में भाजपा–नीत राजग शासन के दौरान रखी।

भारतीय जनसंघ ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में कश्मीर एवं राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दे पर आंदोलन छेड़ा तथा कश्मीर को किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार देने का विरोध किया। नेहरू के अधिनायकवादी रवैये के फलस्वरूप डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी को कश्मीर की जेल में डाल दिया गया जहां उनकी रहस्यपूर्ण स्थिति में मृत्यु हो गई। एक नई पार्टी को सशक्त बनाने का कार्य पण्डित दीनदयाल उपाध्याय के कंधों पर आ गया। भारत–चीन युद्ध में भी भारतीय जनसंघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर नेहरू की नीतियों का डट कर विरोध किया। 1967 में पहली पर भारतीय जनसंघ एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में भारतीय राजनीति

पर से कांग्रेस का एकाधिकार टूटा जिससे कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार हुई।

भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय

सत्तर के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में निरंकुश होती जा रही कांग्रेस सरकार के विरूद्ध देश में जन–असंतोष उभरने लगा। गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन के साथ ही बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हो गया। कांग्रेस ने इन आंदोलनों के दमन का रास्ता अपनाया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया तथा देशभर में कांग्रेस शासन के विरूद्ध जन–असंतोष मुखर हो उठा। 1971में देश पर भारत–पाक युद्ध तथा बांग्लादेश में विद्रोह के परिप्रेक्ष्य में बाह्य आपात्काल लगाया गया था जो युद्ध समाप्ति के बाद भी लागू था। इसे हटाने की भी मांग तीव्र होने लगी। जनान्दोलनों से घबरा कर इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने जनता की आवाज को दमनचक्र से कुचलने का प्रयास किया। 25 जून 1975 को देश पर दूसरी बार आपात्काल भारतीय संविधान की धारा 352 के अंतर्गत 'आंतरिक आपात्काल' के रूप में थोपा गया। देश के सभी बड़े नेता या तो नजरबंद कर दिये गए अथवा जेलों में डाल दिए गये। समाचार पत्रों पर 'सेंसर' लगा दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत अनेक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हजारों कार्यकर्ताओं को 'मीसा' के अंतर्गत गिरतार कर जेल में डाल दिया गया। देश में लोकतंत्र पर खतरा मंडराने लगा। जनसंघर्ष को भी तेज किया जाने लगा, भूमिगत गतिविधियां भी तेज हो गईं। तेज होते जनान्दोलनों से घबरा कर इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी 1977 को लोकसभा भंग कर दी तथा नये जनादेश प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर एक नया राष्ट्रीय दल ''जनता पार्टी'' का गठन किया गया। विपक्षी दल एक मंच से चुनाव लड़ें तथा चुनाव में कम समय होने के कारण 'जनता पार्टी' का गठन पूरी तरह से राजनीतिक दल के रूप में नहीं हो पाया। आम चुनावों में कांग्रेस की करारी हार हुई तथा 'जनता पार्टी' एवं अन्य विपक्षी पार्टियां भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई। पूर्व घोषणा के अनुसार 1 मई 1977 को भारतीय जनसंघ ने करीब 5000 प्रतिनिधियों के एक अधिवेशन में अपना विलय जनता पार्टी में कर दिया।

भाजपा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित 'एकात्म–मानवदर्शन' को अपने वैचारिक दर्शन के रूप में अपनाया है। साथ ही पार्टी अंत्योदय, सुशासन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास एवं सुरक्षा पर भी विशेष रूप से सक्रिय है। पार्टी ने पांच प्रमुख सिद्धांतों के प्रति भी अपनी निष्ठा व्यक्त की जिन्हें 'पंचनिष्ठा' कहते हैं। ये पांच सिद्धांत (पंचनिष्ठा) हैं– राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय अखंडता, लोकतंत्र, सकारात्मक पंथ–निरपेक्षता (सर्व–धर्म समभाव), गांधीवादी समाजवाद (सामाजिक–आर्थिक विषयों पर गांधीवादी दृष्टिकोण द्वारा शोषण मुक्त समरस समाज की स्थापना) तथा मूल्य–आधारित राजनीति।

भाजपा का गठन

जनता पार्टी का प्रयोग अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। दो–ढाई वर्षों में ही आन्तरिक अंतर्विरोध सतह पर आने लगा। कांग्रेस ने भी जनता पार्टी को तोड़ने में राजनीतिक दांव–पेंच खेलने से परहेज नहीं किया। भारतीय जनसंघ से जनता पार्टी में आये सदस्यों को अलग–थलग करने के लिए 'दोहरी–सदस्यता' का मामला उठाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रखने पर आपत्तियां उठायी जानी लगी। यह कहा गया कि जनता पार्टी के सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नहीं बन सकते। 4 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति ने अपने सदस्यों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य होने पर प्रतिबंध लगा दिया। पूर्व के भारतीय जनसंघ से संबद्ध सदस्यों ने इसका विरोध किया और जनता पार्टी से अलग होकर 6 अप्रैल 1980 को एक नया संगठन भारतीय जनता पार्टी के नाम से घोषणा की गई। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई।

विचार एवं दर्शन

भारतीय जनता पार्टी एक सुदृढ़, सशक्त, समृद्ध, समर्थ एवं स्वावलम्बी भारत के निर्माण के लिए निरंतर सक्रिय है। पार्टी की कल्पना एक ऐसे राष्ट्र की है जो आधुनिक दृष्टिकोण से युक्त एक प्रगतिशील एवं प्रबुद्ध समाज का प्रतिनिधित्व करती हो तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति तथा उसके मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए महान 'विश्वशक्ति' एवं 'विश्व गुरू' के रूप में विश्व पटल पर स्थापित हो। इसके साथ ही विश्व शांति तथा न्याययुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विश्व के राष्ट्रों को प्रभावित करने की क्षमता रखे।

भाजपा भारतीय संविधान में निहित मूल्यों तथा सिद्धांतों के प्रति निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित राज्य को अपना आधार

मानती है। पार्टी का लक्ष्य एक ऐसे लोकतंत्रीय राज्य की स्थापना करना है जिसमें जाति, सम्प्रदाय अथवा लिंग भेद–भाव किए बिना सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, समान अवसर तथा धार्मिक विश्वास एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो।

भाजपा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित 'एकात्म–मानवदर्शन' को अपने वैचारिक दर्शन के रूप में अपनाया है। साथ ही पार्टी अंत्योदय, सुशासन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास एवं सुरक्षा पर भी विशेष रूप से सक्रिय है। पार्टी ने पांच प्रमुख सिद्धांतों के प्रति भी अपनी निष्ठा व्यक्त की जिन्हें 'पंचनिष्ठा' कहते हैं। ये पांच सिद्धांत (पंचनिष्ठा) हैं– राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय अखंडता, लोकतंत्र, सकारात्मक पंथ–निरपेक्षता (सर्व–धर्म समभाव), गांधीवादी समाजवाद (सामाजिक–आर्थिक विषयों पर गांधीवादी दृष्टिकोण द्वारा शोषण मुक्त समरस समाज की स्थापना) तथा मूल्य–आधारित राजनीति।

उपलब्धियां

श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अपनी स्थापना के साथ ही भाजपा राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गई। बोफोर्स एवं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पुनः गैर–कांग्रेसी दल एक मंच पर आये तथा 1989 के आम चुनावों में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। वी.पी. सिंह के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को भाजपा ने बाहर से समर्थन दिया। इसी बीच देश में राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू हुआ। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए रथयात्रा शुरू की। राम मंदिर के लिए भारी जनसमर्थन एवं भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा कर रथ यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया, फलतः भाजपा ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। वी.पी. सिंह की सरकार गिर गई तथा कांग्रेस के समर्थन से चन्द्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने। आने वाले आम चुनावों में भाजपा का जनसमर्थन लगातार बढ़ता गया। इसी बीच नरसिम्हाराव के नेतृत्व में कांग्रेस तथा कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चे की सरकारों का शासन देश पर रहा जिस दौरान भ्रष्टाचार, अराजकता एवं कुशासन के कई 'कीर्तिमान' स्थापित हुए।

1996 के आम चुनावों में भाजपा को लोकसभा में 161 सीटें प्राप्त हुईं। भाजपा ने लोकसभा में 1989 में 85, 1991 में 120 तथा 1996 में 161 सीटें प्राप्त कीं। भाजपा का जनसमर्थन लगातार बढ़ रहा था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बार भाजपा सरकार ने 1996 में शपथ ली परन्तु पर्याप्त समर्थन के अभाव में यह सरकार मात्र 13 दिन ही चल पाई। 1998 के आम चुनावों में भाजपा ने 182 सीटों पर जीत दर्ज की।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने शपथ ली। परन्तु जयललिता के नेतृत्व में अन्नाद्रमुक द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण सरकार लोकसभा में विश्वासमत के दौरान एक वोट से गिर गई जिसके पीछे वह अनैतिक आचरण था, जिसमें उड़ीसा के कांग्रेसी मुख्यमंत्री गिररिधर गोमांग पद पर रहते हुए भी उन्होंने लोक सभा की सदस्यता नहीं छोड़ी तथा विश्वासमत पर सरकार के विरूद्ध मतदान किया। कांग्रेस के इस अवैध और अनैतिक आचरण के कारण ही देश को पुनः आम चुनावों के दौर से गुजरना पड़ा। 1999 में भाजपा 182 सीटों पर पुनः विजय हुई तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 306 सीटें प्राप्त हुईं। एक बार पुनः श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा–नीत–राजग की सरकार बनी।

भाजपा–नीत–राजग सरकार ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में विकास के अनेक नये प्रतिमान स्थापित किये। पोखरण विस्फोट, अग्नि–प्प का प्रक्षेपण, कारगिल विजय जैसी सफलताओं से भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऊंचा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, जनवितरण प्रणाली में सुधार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में नये पहल एवं प्रयोग, कृषि, विज्ञान एवं उद्योग के क्षेत्रों में तीव्र विकास के साथ–साथ महंगाई न बढ़ने जैसी अनेकों उपलब्धियां इस सरकार के खाते में दर्ज है।

भारत–पाक संबंधों को सुधारने, देश की आंतरिक समस्याओं जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तर–पूर्व में राज्यों में अलगाववाद पर कई प्रभावी कदम उठाए गये। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को सुदृढ़ कर सुशासन एवं सुरक्षा को केन्द्र में रख देश को समृद्ध एवं समर्थ बनाने की दिशा में अनेक निर्णायक कदम उठाये गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राजग शासन ने देश में विकास की एक नई राजनीति का सूत्रपात किया।

वर्तमान स्थिति

भाजपा वर्तमान में लोकसभा एवं राज्य सभा दोनों में प्रमुख विपक्षी दल है। छः राज्यों में भाजपा की अपनी सरकार है तथा अन्य तीन राज्यों में यह अपने मित्र दलों के साथ शासन चला रही है। आज भाजपा देश में एक प्रमुख राष्ट्रवादी शक्ति के रूप में उभर चुकी है एवं देश के सुशासन, विकास, एकता एवं अखंडता के लिए कृतसंकल्प है।■

मध्यप्रदेश का विकास मॉडल अनुकरणीय : अरुण जेटली

महाकाल की नगरी उज्जैन के मित्तल एवेन्यू परिसर के सालिगराम तोमर सभागृह में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अनंत कुमार ने दीप प्रज्जवलन कर पं. दीनदयाल उपाध्याय, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया, तत्पश्चात वंदे मातरम का गायन हुआ। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा, राष्ट्रीय महासचिव नरेन्द्रसिंह तोमर, थावरचन्द गेहलोत, अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तनवीर अहमद, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष फग्गनसिंह कुलस्ते, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, प्रदेश संगठन महामंत्री अरविन्द मेनन, उज्जैन महापौर रामेश्वर अखण्ड उपस्थित थे। प्रदेश महामंत्री नंदकुमारसिंह चौहान ने बैठक का संचालन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने प्रथम सत्र में अध्यक्षीय उदबोधन दिया।

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का उदघाटन करते हुए राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अनंत कुमार ने कहा कि केन्द्र की सरकार भले ही बहुमत में हो लेकिन यूपीए का गठबंधन बिखराव की ओर है। देश में मध्यावति चुनाव होंगे और भाजपा की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनेगी। राहुल गांधी का कथित जादू समाप्त हो गया है। बिहार के विधानसभा चुनाव इसका उदाहरण है। दिल्ली में सत्ता का रास्ता भोपाल से होकर जायेगा। आने वाले मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर हमें विजयी होने का लक्ष्य रखना होगा। उन्हांने कहा कि मध्यप्रदेश आज बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर निकल चुका है और देश के प्रगतिशील और विकसित राज्य के साथ आ चुका है।

सामाजिक रिश्ते कायम करने के लिए करीब दो हजार कार्यकर्ता वर्ष के अंत तक 20 हजार गांवों में पहुंचेंगे। जो ग्रामीणों को प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से अवगत करवाने के साथ केंद्र सरकार की विफलताओं से रूवरू करवाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक महीने में इंदौर, भोपाल, जबलपुर और सागर में सेमिनार आयोजित किए जाएंगे।

अनंत कुमार ने कहा कि मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा की अगुवाई में संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। सरकार की कई योजनाओं को अन्य सरकारों ने भी स्वीकार किया है।

अनंत कुमार ने कहा कि मध्यप्रदेश में भाजपा संगठन पूरे देश के लिए

आदर्श है। यहां के कार्यकर्ता बहुत योग्य है। बिहार विधानसभा चुनाव में इन कार्यकर्ताओं ने अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित भी किया है तभी वहां पर भाजपा ने अपने 102 प्रत्याशियों को खडा किया था जिसमें 91 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। आपने आव्हान किया कि मध्यप्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने इसलिए हमें संकल्प लेना है।

कार्यसमिति बैठक के दूसरे दिन समापन समारोह को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरूण जेटली ने पार्टी में काम और पद की जिम्मेदारी योग्यता के आधार पर सौंपने की वकालत की। इसकी शुरूआत उन्होंने मध्यप्रदेश से करने की इच्छा जताई।

उन्होंने मध्यप्रदेश में हुए विकास कार्यों कें लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व उनकी सरकार की दिल खोलकर तारीफ की। जेटली ने मप्र के विकास और जनहित के मॉडल को देश के दूसरे राज्यों के अनुसरण योग्य करार दिया। उन्होंने कहा कि जनता के बीच में एक बार जो छवि बन गई है उसे कायम रखना बेहद जरूरी है। जेटली ने कहा कि चुनाव के लिए दो बातें जरूरी होती हैं। पहली सरकार का काम ऐसा हो जिसकी स्वीकृति जनता में हो और दूसरा यह कि नेतृत्व साफ–सुथरा यानी बेदाग हों। मप्र में जीत व विकास के पीछे शिवराज की अच्छी छवि बड़ा कारण है। सत्ता और संगठन की दृष्टि से इस प्रांत में भविष्य अच्छा रहेगा।

जेटली ने भ्रष्टाचार व घोटालों के उदाहरण देते हुए प्रतिनिधियों को यह समझाइश देने की कोशिश भी कि अब केंद्र की सरकार से जनता का विश्वास उठता जा रहा है। तीव्र विकास और गैर विवादित शासन के लिए उन्होंने राजनीति में वंशवाद को बढ़ने से रोकने की बात कहते हुए योग्यता आधारित लोगों को अवसर देने की बात कही।

समापन समारोह में प्रदेशाध्यक्ष प्रभात झा ने कहा कि सामाजिक रिश्ते कायम करने के लिए करीब दो हजार कार्यकर्ता वर्ष के अंत तक 20 हजार गांवों में पहुंचेंगे। जो ग्रामीणों को प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से अवगत करवाने के साथ केंद्र सरकार की विफलताओं से रूवरू करवाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक महीने में इंदौर, भोपाल, जबलपुर और सागर में सेमिनार आयोजित किए जाएंगे।

बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, वरिष्ठ नेता कैलाश सारंग, विक्रम वर्मा, सुमित्रा महाजन, डॉ. सत्यनारायण जटिया, प्रो.कप्तानसिंह सोलंकी, माखनसिंह चौहान, भगवतशरण माथुर, अनिल माधव दवे, बाबूलाल गौर, राघवजी भाई, गोपाल भार्गव, कैलाश विजयवर्गीय, अजय विश्नोई, जगदीश देवडा, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विजय शाह, गौरीशंकर बिसेन, जगन्नाथ सिंह, अर्चना चिटनीस, रंजना बघेल, माया सिंह, रघुनंदन शर्मा, अनुसुईया उइके, राकेश सिंह, भूपेन्द्र सिंह, रामपाल सिंह, उषा चतुर्वेदी, अंजु माखीजा, उषा ठाकुर, गौरीशंकर शेजवार, ध्रुवनारायण सिंह, कुंवर सिंह, अरविन्द भदौरिया, रामेश्वर शर्मा, गणेश सिंह, सरिता देशपाण्डे, ओमप्रकाश खटीक, दशरथ सिंह लोधी, नागरसिंह चौहान, ज्योति येवतिकर, राजो मालवीय, तपन भौमिक, विजेश लुनावत, डॉ. हितेश वाजपेयी, आलोक संजर सहित प्रदेश कार्यसमिति सदस्य उपस्थित थे। ■

पृष्ठ 21 का शेष

कुछ किया जा रहा है, वह सामान्य कर संग्रहण है जो कि 20 करोड़ से भी कम है। इसका काले धन से कोई लेना देना नहीं है।

सरकार को इस संबंध में एक रूपरेखा बनानी चाहिए कि किस तरह सरकार द्वारा सभी खरीद प्रक्रियाओं को अपनाया जा रहा है और किस तरह प्राकृतिक संसाधनों को आवंटित किया जा रहा है?

सरकार एक प्रावधान लायी है, जिसके अंतर्गत विदेशी कंपनी से लाए लाभांशों पर 15 प्रतिशत की कम दर पर कर लगाया जाएगा। यह सरकार द्वारा शुरू की गई अप्रत्यक्ष रूप से छूट योजना है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये लाभांश वास्तविक आय से प्राप्त हैं और यह गुप्त धन नही है, जिसे लाभांश के रूप में लाया जा रहा है। इस सरकार की 'एसईजेड' नीति शुरू से ही पूरी तरह विफल रही है। सरकार को पिछड़े क्षेत्रों में वास्तविक अवसंरचना विकास कर्ताओं पर कर नहीं लगाना चाहिए। इसके बजाय, केवल 'अचल संपदा विकासकर्ताओं' पर कर लगाना चाहिए।

सरकार को कर मुकदमों के समाधान के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। इस सरकार को कर विभाग में कंप्यूटरीकरण की समस्या के समाधान पर भी ध्यान देना चाहिए। मॉरिशस के माध्यम से डीटीए संधि का दुरूपयोग किया जा रहा है। मॉरिशस को कर लाभ दें परंतु केवल वास्तविक निधियों के लिए। राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं से, संरक्षित किया जाना चाहिए। उनकी राजकोषीय स्वायत्तता को संरक्षित करने के लिए कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। मुद्रास्फीति की दर इस सरकार की गलत नीतियों के कारण पिछले पांच वर्षों के दौरान 12 प्रतिशत पहुंच गई है। ■

उत्तर प्रदेश

हमारी मांग प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो : सूर्य प्रताप शाही

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री सूर्य प्रताप शाही ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए क्योंकि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी है और आम आदमी का जीवन खतरे में पड़ गया है। आए दिन हत्याएं होती रहती है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है और फिर उन्हें मार दिया जाता है। विद्यार्थियों को पुलिस की बर्बरता सहनी होती है और सरकारी अधिकारी किसानों के प्रति उदासीन रहते हैं।

ऐसी स्थिति में और कोई विकल्प नहीं बचा रहता है, सिवाय इसके कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। श्री शाही ने यह वक्तव्य 17 मार्च को जारी किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने मुलायम राज का कुशासन भी देखा और अब उन्हें मायावती राज की आग में झुलसना पड़ रहा है। भाजपा ही केवल स्वच्छ और कुशल प्रशासन दे सकती है और भाजपा ही देश में कानून का ही शासन ला सकती है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो हम मुलायम सिंह और मायावती की संपत्तियों की जांच कराएंगे। उनकी पार्टी चीफ इंजीनियरों में एक व्यक्ति ने मुलायम राज की पोल खोली और अब मायावती के शासन में देखा गया है कि यह संपत्ति 400 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति है। इससे पता चलता है कि ये सरकारें भ्रष्ट और जन–विरोधी सरकारें रही हैं।

वे खुशीनगर जिला में समाही गांव में मारे गए प्रधान लल्लन कुशवाहा के परिजनों से भी मिले जिनकी खुलेआम गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।

हिमाचल प्रदेश

केन्द्र भाजपा -शासित राज्यों के प्रति रखता है भेदभाव : नड्डा

भाजपा राष्ट्रीय महासचिव श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 17 मार्च को कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही केन्द्र सरकार भाजपा शासित राज्यों के साथ पूरे देश भर में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं। यह सचमुच अत्यंत दुखद और खेदपूर्ण है।

सदन को संबोधित करते हुए और बजट पर अपने विचार प्रकट करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि यूपीए सरकार को हिमाचल प्रदेश में कायम रखने के लिए विशिष्ट धनराशि देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में राज्य सरकार को पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए हर तरफ से सराहना की जा रही है। देश में हमारा पहला राज्य है जहां प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया और हमने जिस प्लास्टिक का संग्रह किया ,उसका उपयोग पीडब्लयूडी ने राज्य सड़क –निर्माण में किया। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य को विश्व भर में 'इकोलॉजी' की रक्षा के लिए व्यापक प्रशंसा मिल रही है परन्तु यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केन्द्र में कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार पर्यावरण की रक्षा करने के हमारे प्रयासों की तरफ अपनी आंखें मुंदे रहती है।

उन्होंने कांग्रेसी विधायकों से भी कहा कि वे राजनीतिक आधार से ऊपर उठकर केन्द्र से हिमाचल के हिस्से की धनराशि प्राप्त करने के लिए संयुक्त रूप से काम करें।

श्री नड्डा ने केन्द्र सरकार से हिमाचल को विशेष धनराशि प्रदान करने की मांग की ,जैसा कि केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वायदा किया था। आज हम पर्यावरण की रक्षा के पैरामीटर के आधार पर देश में दूसरे नंबर पर खड़े हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह अत्यंत खेद का विषय है कि जिन राज्यों ने पर्यावरण सुरक्षित करने का काम किया है ,जिसके लिए 3000 करोड़ रुपये की राशि दी जानी थी ,उसमें से आज तक एक पैसा भी दिया नहीं गया। इसके लिए हमारी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए और पूरे देश में हमारे राज्य में पर्यावरण सेवाओं में जो योगदान दिया है, उसकी धनराशि हमें तुरंत मिलनी चाहिए। ■